राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 05 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-275 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

सीईसी ज्ञानेश पर 20 साल पुराने आरोप की होगी जांच

● केरलम में 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का लगा था आरोप

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। केरलम के गृहमंत्री मेश चेन्निथला ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य में पीडब्ल्यूडी सचिव थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पेमेंट करने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस समय कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने यहां 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। साजन के मुताबिक, इंजीनियरों ने करीब 17 करोड़ के बिल मंजूर कर दिए थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने चेक रोक दिए। इससे मलेशियाई कंपनी उसके ठेकेदारों और कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हुई। कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें (साजन को) बताया था कि ज्ञानेश कुमार रिश्वत मांगे बिना भुगतान के चेक जारी नहीं कर रहे हैं।



लोकतंत्र में धरना और भूख हड़ताल की जगह नहीं

● हाईकोर्ट बोला-यूनिवर्सिटी राजनीति नहीं,पढ़ाई की जगह

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों की संवैधानिक लोकतंत्र में जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा- शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत



यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित छात्रों के मामले में की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब 16 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े इन छात्रों ने परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे उनका पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो सकता है। यूनिवर्सिटी में 13 अगस्त को सिंडिकेट की बैठक के दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वे कैंपस में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पानी की समस्या और शिक्षकों के खाली पद भरने जैसी 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

होसबाले बोले-हमने पूरा किया आरएसएस का संकल्प

हमें राम मंदिर बनाकर दिखाना था, वह हमने बना दिया:संघ

इंदौर में सरकार्यवाह ने कहा-आरक्षण को लेकर न हो राजनीति



इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। डेली कॉलेज में 2 नवंबर से चल रही इस बैठक में देशभर से करीब 400 प्रतिनिधि शामिल हुए। समापन के बाद सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने आरक्षण, मंदिरों के मामलों, संगठन विस्तार, एसआईआर, संघ के पंजीयन और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संघ का पक्ष रखा। आरक्षण पर होसबाले ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जब तक समान अवसर नहीं मिलते, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसका लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि समेत अदालतों में चल रहे मंदिरों के मामलों पर उन्होंने कहा, 'हमें राम मंदिर बनाकर दिखाना था, वह हमने बना दिया।

एक साल में 10,241 नए स्थानों तक पहुंचा संघ

होसबाले ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में संगठन का विस्तार हुआ है। एक साल में संघ की पहुंच 10,241 नए स्थानों तक बढ़ी है। अब देश के 63,208 स्थानों पर 99,423 शाखाएं संचालित हो रही हैं।

मोबाइल से दूर रखने के बजाय बच्चों को संस्कार दें

नए जनसंचार माध्यमों और मोबाइल के इस्तेमाल पर होसबाले ने कहा कि तकनीक को रोकना आसान नहीं है। बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल से पूरी तरह दूर रखने के बजाय उन्हें सही संस्कार देना जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है। माता-पिता को तय करना चाहिए कि बच्चों को किस उम्र में डिवाइस देना है और वे कितनी देर उसका इस्तेमाल करें। उन्होंने परिवारों से अपील की कि दिन में या सप्ताह में आधा से एक घंटा मोबाइल से दूर रहकर सभी सदस्य साथ बैठें और सकारात्मक विषयों पर बातचीत करें। मंदिर जाने वाले लोग बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें धार्मिक-सामाजिक परंपराओं का महत्व समझाएं।

बंगाल में 150 गुना बढ़ीं शाखाएं,केरल के हर गांव तक पहुंचने का दावा

संघ की शाखाओं के विस्तार पर होसबाले ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शाखाओं की संख्या पहले की तुलना में 150 गुना बढ़ी है। पहले वहां शाखाएं लगाने का विरोध होता था। त्रिपुरा और असम में संघ के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, लेकिन संगठन का काम जारी रहा। मिजोरम में दो जगह और लद्दाख में भी शाखाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि केरल के सभी गांवों में संघ की शाखाएं हैं। होसबाले ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए संघ विशेष योजना बनाएगा।

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हारे राष्ट्रपति ट्रंप

● दोनों सदनों में करारी हार,डेमोक्रेट्स को बहुमत ● पहले मुस्लिम सीनेटर बनेंगे अब्दुल अल-सैयद ● चुनाव प्रचार में ट्रम्प ने उन्हें 'जिहादी' कहा था

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं, मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद ने जीत हासिल की। इसके साथ ही वह अमेरिकी इतिहास में सीनेटर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। ट्रम्प ने अब्दुल को खुले मंच से जिहादी कहा था। 25 अक्टूबर को मिशिगन में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रम्प ने कहा था,मैं यहां एक जिहादी और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोकने आया हूं।



हार के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद बाजार में यह अनिश्चितता बढ़ी है कि ट्रम्प ईरान युद्ध को लेकर आगे क्या फैसला लेंगे। इसी चिंता का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक, बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत 76 सेंट यानी 0.7 फीसदी बढ़कर 104.36 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनेट सब हारे

हाउस में कुल 435 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव हुए हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 231 सीटें जबकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने 144 सीटें जीती हैं। सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 33 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। बाकी 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं।

राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर जबरदस्त ब्लास्ट

45 मिनट पहले पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी, बाल-बाल बची



अनूपगढ़ (एजेंसी)। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे लाइन पर मंगलवार रात 9.45 बजे ब्लास्ट हो गया। अनूपगढ़-सूरतगढ़ ट्रैक पर धमाके से पहले रात 9 बजे पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी। धमाके की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के कारण पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो ब्लॉक पूरी तरह से टूट गए। पटरियों के बीच 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

दुनिया का छठा प्रोजेक्ट

नवी मुंबई में बन रही देश की पहली समुद्री रेल-टनल

● 7 किलोमीटर लंबी, 35 मंजिला इमारत जितनी गहराई में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

सावली (एजेंसी)। नवी मुंबई के सावली में देश की पहली समुद्री रेल सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग से देश की पहली बुलेट ट्रेन गुजरेगी। सुरंग बनाने का काम जमीन से 114 मीटर नीचे चल रहा है, यानी इतनी गहराई, जितनी 35 मंजिला ऊंची इमारत होती है। समुद्र के अंदर सुरंग बनाने का यह छठा प्रोजेक्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 समुद्री सुरंगें जापान में हैं। इसके अलावा चीन, नॉर्वे में एक-एक समुद्री सुरंग है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी एक समुद्री सुरंग बनी है।



भारी गर्मी और घुटन के बीच करीब 1,200 मजदूर और इंजीनियर दिन-रात इस काम में जुटे हैं। सावली से शीलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग पहले ही तैयार हो चुकी है। अब समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जा रही है, जिसके लिए 3,000 टन भारी मशीन लगातार खुदाई कर रही है। आमतौर पर मेट्रो के आने-जाने के लिए दो अलग सुरंगे बनती हैं, लेकिन यहां एक ही चौड़ी सुरंग के अंदर से दोनों तरफ की बुलेट ट्रेनें एक साथ निकलेंगी।

पानी का दबाव और कंपन रोकना बड़ी चुनौती

विक्रोली से बीकेसी के बीच इमारतों, फ्लाईओवरों को कंपन से बचाने के लिए टीबीएम की गति 4 आरपीएम पर सेट है। जमीन पर रियल-टाइम सेटलमेंट सेंसर 24 घंटे हलचलों की निगरानी कर रहे हैं। पानी का दबाव : गीली मिट्टी और भारी जलदाब के कारण समुद्री सुरंग में पानी भरने का जोखिम है। इससे बचने स्लरी बेस्ड मिक्स शील्ड टीबीएम चल रही है, जो मिट्टी-पानी के गाढ़े घोल की मदद से खुदाई कर रही है। 13.6 मीटर व्यास वाली विशाल सुरंग एनएटीएम तकनीक से खोदते तो इसके ढहने की आशंका ज्यादा थी। इसलिए टीबीएम से खुदाई के साथ ही कंक्रीट रिंग सेगमेंट्स और वाटरप्रूफ सीलिंग लगा रहे हैं।

दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव से रोकना गलत

● सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कानून पर विचार की है जरूरत ● देश के 5 राज्यों में लागू है नियम, कई और में तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। इससे कम प्रजनन दर का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर में गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को राहत दी।



मौजूदा कानून राजनीतिक अधिकारों से वंचित करते हैं

बेंच ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर कर देते हैं। इसका किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई खास संबंध नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे कानून लोगों को बच्चे पैदा करने या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करते हैं। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन से जुड़े फैसले लेने की आजादी के अधिकार का उल्लंघन होता है। मंगला भीमराव महाराष्ट्र की काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच थीं।

7 राज्यों ने दो बच्चों की शर्त खत्म की

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील रुक्मिणी बोबडे को कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। कोर्ट ने उनसे और याचिकाकर्ता के वकील प्रतीक बोरंबडे से उन राज्यों की सूची मांगी थी, जहां दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक है। रुक्मिणी बोबडे की ओर से दी गई सूची के मुताबिक, 7 राज्यों ने दो बच्चों की शर्त खत्म कर दी है, जबकि 15 राज्यों में ऐसी कोई नीति नहीं है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड में यह नियम अब भी लागू है। 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दो बच्चों की शर्त को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। इस कानून के तहत दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता था। मौजूदा बेंच ने 4 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

राहुल गांधी ने पीएम को फिर दी बहस की चुनौती

बोले-मोदी देशद्रोही, ट्रम्प के कहने पर काम कर रहे

संगरूर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती दी है। मैंने उन्हें कहा है कि कहीं भी आकर मेरे साथ डिबेट कर लो, लेकिन वह मेरे सामने आकर बैठ नहीं सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 5 मिनट में उन्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा। मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियंत्रित कर रहे हैं। ये बात उन्होंने पंजाब के संगरूर में इंसाफ रैली के दौरान कही। संबोधन की शुरुआत में वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को स्टेज पर लाए। राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ, वह आज पंजाब में एक फैशन बन गया है। पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है।



राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस की सरकार बनाइए

राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब को पंजाब की सरकार दीजिए। कांग्रेस की सरकार दीजिए। ऐसी सरकार चुनिए जो नशे के खिलाफ लड़े, ड्रग्स खत्म करे, युवाओं को रोजगार दे, उद्योगों को बचाए और किसानों के साथ खड़ी रहे।



अग्निवीरों को मोदी सरकार का दीवाली गिफ्ट!

● पचहत्तर फीसदी को मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन ● सीडीएस का ऐलान-सैलरी भी बढ़ेगी,नौकरी पक्की

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा दीवाली गिफ्ट दिया है। केंद्र ने अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि अग्निवीरों को दो साल का और इंगेजमेंट पीरियड मिलेगा। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में भी एनरोलमेंट किया जाएगा। दो साल का पीरियड पूरा होने के बाद ऑब्जेक्टिव सेलेक्शन प्रक्रिया के जरिए उन्हें सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार ने बुधवार को 'अग्निवीरों' को दो साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब करीब 18,000 अग्निवीरों को कुछ सप्ताह बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होना था। सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर दिया जाएगा।



अग्निवीरों को मिलेगा सेवा विस्तार

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आज का दिन भारतीय रक्षा बलों और हमारे अग्निवीरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। उस समय यह बताया गया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी। सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इन चार वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है।

डिफेंस फोर्सेज में नियमित सेवा का भी मौका

सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं। मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा। बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा। इस तरह से 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल एक्सटेंशन-सैलरी भी बढ़ेगी, नौकरी पक्की करने का मौका होगा।

75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन

उन्होंने कहा कि पहले 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौट जाएंगे। हालांकि, इस अपडेट की गई योजना के तहत, बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नदियों की गाद से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार के विकास को मिलेगी नई गति

(लेखक - विनोद सिंह 'तकियावाला')

'नदी संजीवनी' पहल से बाढ़ नियंत्रण, जलाशयों के पुनर्जीवन और सड़क निर्माण को जोड़ने की ऐतिहासिक पहल

बिहार की नदियों में जमा गाद अब राज्य के लिए केवल बाढ़ और जलजमाव की समस्या नहीं रहेगी,बल्कि विकास का नया संसाधन बनने जा रही है। नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई उपयुक्त गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा। इस उद्देश्य से 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हुई यह पहल 'नदी संजीवनी' के माध्यम से जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना के विकास को एक साथ जोड़ती है। इसका लक्ष्य नदियों की जलवहन क्षमता में सुधार, बाढ़ के जोखिम को कम करने और निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना है।बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए इस समझौते का विशेष महत्त्व है। राज्य का बड़ा भूभाग गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। गंगा के साथ गंडक, कोसी, बागमती, कमला-बालन, महानंदा, सोन और पुनपुन जैसी नदियाँ बिहार की जीवनरेखा हैं। नेपाल से आने वाली नदियों में वर्षा के मौसम में जलस्तर बढ़ने और उनके साथ बड़ी मात्रा में गाद आने से राज्य के अनेक जिलों में बाढ़ और जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। नदियों के तल में लगातार जमा होती गाद जलप्रवाह और जलधारण क्षमता को प्रभावित करती है। बिहार में 50 हजार से अधिक जल निकायों की मौजूदगी इस समस्या के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने और उसका उपयोगी पुनः इस्तेमाल करने की पहल जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गाद को अपशिष्ट के बजाय निर्माण कार्य में उपयोगी संसाधन के रूप में देखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आकलन के अनुसार,बिहार में निर्माणाधीन 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में नदियों से निकाली गई लगभग 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग किया जाएगा। भविष्य की 27 परियोजनाओं के लिए लगभग 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है। यह सामग्री तकनीकी परीक्षण और निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने के बाद ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। इससे सड़क निर्माण के लिए मिट्टी की उपलब्धता बढ़ेगी और प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के अनावश्यक दोहन को सीमित करने में मदद मिलेगी।बिहार में इस समय लगभग 1,561 किलोमीटर लंबाई की 39 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत करीब 58,340 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त लगभग 1,982 किलोमीटर लंबाई की 11 नई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 75,200 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री की आवश्यकता होगी। नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई उपयुक्त गाद इस आवश्यकता को पूरा करने में सहायक हो सकती है। इस व्यवस्था से एक ओर जल निकायों की सफाई और पुनर्जीवन को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राजमार्ग निर्माण के लिए स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक जल प्रबंधन, नदियों की ड्रेजिंग, तट संरक्षण और जल ग्रिड की अवधारणा पर जोर देते रहे हैं। पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और बिजली ग्रिड की तर्ज पर जल ग्रिड विकसित करने का विचार रखा था। उनका कहना था कि एक नदी बेसिन में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को दूसरे बेसिन तक पहुँचाने की व्यवस्था से जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने नदियों से गाद निकालकर उसका उपयोग राजमार्ग निर्माण में करने की संभावना भी व्यक्त की थी। अब केंद्र और बिहार सरकार के बीच हुआ यह समझौता उस विचार को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बिहार की गाद प्रबंधन नीति को राज्य के लिए दूरगामी महत्त्व का कदम बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में नेपाल से आने वाली सात प्रमुख नदियों के कारण बाढ़ की चुनौती गंभीर बनी रहती है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक गाद प्रबंधन नीति तैयार की है, ताकि नदियों में जमा गाद को विकास के संसाधन में बदला जा सके। मुख्यमंत्री ने बांका जिले के ओढ़नी बांध का उदाहरण देते हुए बताया कि गाद निकालने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर लगभग 350 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित किए जाने पर एक निजी ठेकेदार ने काम करने के बदले सरकार को 60 करोड़ रुपये देने की पेशकश की। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर गाद प्रबंधन आर्थिक अवसर भी बन सकता है।मुख्यमंत्री ने गंगा के दोनों किनारों पर बिहार में चार लेन के मार्ग विकसित करने की संभावना पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने गंगा के जलमार्गों को व्यवस्थित करने और नदी तल से गाद निकालने के माध्यम से बड़े भूभाग को उपयोगी बनाने की संभावना का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री की दृष्टि में नदी प्रबंधन को बाढ़ नियंत्रण तक सीमित रखने के बजाय कृषि, परिवहन, औद्योगिक विकास और रोजगार से जोड़ना आवश्यक है। हालाँकि, इस प्रकार की व्यापक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले विस्तृत तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक अध्ययन जरूरी होगा, ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।इस पहल की सफलता केवल गाद निकालने की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय सुरक्षा से तय होगी। नदियों और जलाशयों की पहचान, गाद की मात्रा का आकलन, उसकी गुणवत्ता की जाँच और उपयोग की उपयुक्तता निर्धारित करना आवश्यक होगा। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को मंत्रालय तथा भारतीय सड़क कांग्रेस के निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। नदी के तटों, तटबंधों, पुलों और आसपास की बस्तियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। गाद की निकासी, ढुलाई और उपयोग की मात्रा का पारदर्शी रिकॉर्ड तथा नियमित निगरानी इस पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बनाएगी। बिहार सरकार की गाद प्रबंधन नीति और केंद्र के साथ हुए इस समझौते का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब क्रियान्वयन में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।बिहार में सड़क अवसंरचना का विस्तार भी इस पहल को विशेष महत्त्व देता है। वर्ष 2014 के बाद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद राज्य की प्रमुख नदियों पर 29 नए पुलों के निर्माण की दिशा में भी काम हुआ है। बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगभग 49,751 करोड़ रुपये की चार प्रमुख सड़क एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इनमें पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सरिस्ताबाद-दीदारगंज और अनीसाबाद-दीदारगंज खंडों में एलिवेटेड मार्ग, वाराणसी- रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड राजमार्ग तथा गंडक नदी पर पुल निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

'नदी संजीवनी' पहल का व्यापक संदेश यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन विकास की नई संभावनाएँ खोल सकता है। नदियों में जमा गाद को हटाकर जलप्रवाह और जलधारण क्षमता में सुधार करना तथा उपयुक्त सामग्री को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लगाना संसाधनों के पुनः उपयोग का व्यावहारिक उदाहरण है। इससे निर्माण सामग्री की उपलब्धता बढ़ सकती है, उपजाऊ मिट्टी के अनावश्यक दोहन पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है और जल निकायों के पुनर्जीवन को प्रोत्साहन मिल सकता है। बिहार की बाढ़ समस्या का समाधान किसी एक योजना से संभव नहीं है, लेकिन यह पहल नदी प्रबंधन, सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करने का अवसर अवश्य प्रदान करती है। अब जरूरत समयबद्ध कार्ययोजना, पारदर्शी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन की है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इसे धरातल पर सफलतापूर्वक लागू कर पाती हैं, तो बिहार की नदियों की गाद वास्तव में राज्य के विकास की नई संजीवनी बन सकती है।

(स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

गरीबी के आंकड़े

विश्व बैंक की निर्धनता एवं समानता संबंधी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच देश में करीब पचास करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाले गए। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अत्यधिक निर्धन वर्ग के लोगों की संख्या में भी करीब पच्चीस फीसदी की कमी आई है। यह संख्या अब घटकर कुल आबादी की 2.6 फीसदी रह गई है। दावा किया जा रहा है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की तादाद में भारी कमी आ रही है। निस्संदेह, इन आंकड़ों को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा सकती हैं। कहा जा रहा है कि राजग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की इसमें अहम भूमिका रही। लेकिन सवाल यह है कि ये आंकड़े कितने प्रामाणिक हैं और क्या विज्ञान-सम्मत तरीके से लिये गए हैं? अर्थशास्त्र में आंकड़ों को लेकर एक मशहूर उक्ति है- 'आंकड़े ऐसी कच्ची मिट्टी है, जिससे देवता और दैत्य दोनों बनाए जा सकते हैं।' यानी सरकारें उनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकती हैं। हालांकि, गरीबी में कमी की यह शुरुआत संप्रग सरकार के समय के आंकड़ों के साथ की गई है। जिसकी समयावधि वर्ष 2011 से शुरू होती है। राजग सरकारों के कार्यकाल में जरूर अधिक समय को अध्ययन में शामिल किया गया है। जिसमें निर्धनता की आई कमी के कारणों में खपत में वृद्धि, रोजगार और खासकर महिलाओं के रोजगार में वृद्धि, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा खाद्य सब्सिडी जैसे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। लंबे समय से देश राजनेताओं के गरीबी हटाओ के नारों व कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। लेकिन उन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि गरीब कल्याण की योजनाओं का कितने कारगर ढंग से क्रियान्वयन हुआ। कितनी ईमानदारी से गरीब के हाथ में कल्याण योजनाओं की राशि पहुंची। बहरहाल, राजग सरकार का दावा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को इससे बाहर निकालने में जन-धन योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,घर-घर शौचालय, घर-घर नल व आयुष्मान योजना की बड़ी भूमिका रही है। एक समय था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि लोककल्याण के कार्य हेतु आवंटित हुए एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह प्रतिशत ही जरूरतमंद के हाथ में पहुंचता है। हालांकि, न खाऊंगा और न खाने दूंगा के उद्घोष के बाद वास्तविक स्थिति में क्या बदलाव आया, यह अध्ययन का विषय होना चाहिए। हालांकि, विपक्षी नेता इस स्थिति के बावजूद मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम की जरूरत को लेकर भी सवाल उठाते हैं। यह सुखद है कि देश में कुछ जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिला। लेकिन देश में अक्सर यह सवाल उठाया जाता रहा है कि जब भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, तो लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव क्यों नहीं आता? क्यों देश में अमीरी-गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है? सही मायने में किसी देश में होने वाला विकास न केवल तर्कसंगत होना चाहिए, बल्कि न्यायसंगत भी होना चाहिए। वैसे यदि वास्तव में आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबी में कमी आई है तो यह हमारे लिये उत्साहजनक स्थिति है। यह जानते हुए कि इस अवधि में हमने कोरोना का भयावह काला दौर देखा था।

क्या ज्ञानेश कुमार को हटा पायेगा इण्डिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन

(लेखिका- निर्मल रानी)

गत 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इण्डिया गठबंधन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली में विपक्षी दलों की भारी एकजुटता देखने को मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ बुलाई गई इस रैली में देश के कई प्रमुख दलों के शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा लिया। इस रैली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। इसके अलावा वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल, डी.के. शिवकुमार और अभिषेक मनु सिंघवी भी मंच पर मौजूद रहे। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस रैली में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ़ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विपक्ष की इस महारैली में विशेष रूप से शामिल हुईं। तथा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और युवा नेता तेजस्वी यादव ने मंच से रैली को संबोधित किया। इसी तरह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला,आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व अन्य कई विपक्षी दलों के अनेक वरिष्ठ नेता इस विशाल रैली को संबोधित करते या सम्मिलत होते दिखाई दिए।

इस रैली में कॉकरोच जनता पार्टी की भी बाहरी तौर पर एक बड़े रैली समर्थक संगठन की सक्रिय भूमिका नज़र आई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रैली से ठीक पहले सोशल मीडिया पर आधिकारिक घोषणा करते हुए इस रैली को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। सीजेपी का मुख्य एजेंडा भी देश में चुनावी शुचिता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाना रहा है। इस महारैली में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख छात्र नेता नेहा बोरा और उनके संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आक्रामक रही। इस रैली के ज़रिए नेहा बोरा मुख्यधारा की राजनीति के बड़े विपक्षी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़े युवा चेहरे के रूप में उभरी हैं। नेहा बोहरा ने तो अपने संक्षिप्त परन्तु तीखा भाषण देते हुये सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निष्पक्ष होने के बजाय सत्ता पक्ष का इलेक्शन मैनेजर क़रार दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर न केवल महाभियोग चलना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए।

परन्तु सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन का यह विशाल शक्ति प्रदर्शन सरकार पर इतना दबाव डाल सकेगा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दे ? निश्चित रूप से इण्डिया गठबंधन के पास पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ताज़ातरीन उदाहरण है जिन्हें गत 25 जुलाई 2026 को भारी सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के चलते त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय अभूतपूर्व जन-आक्रोश और देशव्यापी दबाव को देखते हुए ही धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। यह नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में जनता के सीधे दबाव में किसी बड़े कैबिनेट मंत्री के इस्तीफ़े का एक विरल उदाहरण माना जाता है। निःसंदेह धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद गत 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इण्डिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली भी भारतीय राजनीति के लिहाज़ से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस रैली के ज़रिए विपक्ष ने ईवीएम के साथ-साथ सीधे मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर और लगभग 13.2 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए जाने के मुद्दे को देश के राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। इससे भविष्य के चुनावों विशेषकर 2027 के उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनावी शुचिता पर बड़ी बहस छिड़ गयी है। इस रैली से ठीक पहले 31 अक्टूबर को विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक जनता द्वारा महाभियोग प्रस्ताव भी पारित किया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था के बजाय सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है।

तो क्या इतने सुबूतों व इतने दबाव के बाद ज्ञानेश कुमार जल्द हटाए जा सकते हैं? वास्तव में सरकार व ज्ञानेश कुमार पर अभूतपूर्व दबाव होने के बावजूद संवैधानिक प्रावधानों और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना बेहद जटिल नज़र आता है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही बेहद कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास होना ज़रूरी है। वर्तमान में संसद के समीकरणों को देखते हुए विपक्ष के पास अकेले इस तरह का बहुमत भी नहीं है। हाँ अगर न्यायालय इस प्रक्रिया में कोई गंभीर ख़ामी पाता है, तो ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने पर नैतिक संकट खड़ा हो सकता है। परन्तु सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने साफ़ किया है कि इस रैली की गूंज संसद में दिखाई देगी और वे ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ औपचारिक महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे।

केंद्र सरकार,भारतीय जनता पार्टी और खुद चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध और पारदर्शी बताया है। जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग के अंदर ही अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फ़ैसलों पर 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। परन्तु विपक्ष के इन आरोपों व सत्ता के बचाव की दलीलों के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक या तो सरकार स्वयं बैकफुट पर नहीं आती या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई सख़्त निर्णय अथवा टिप्पणी नहीं आती तब तक केवल विपक्ष के दबाव में किसी संवैधानिक प्रमुख को हटाना संभव नहीं लगता। क्योंकि ज्ञानेश कुमार के हटने के फ़ौरन बाद ही केंद्र सहित विभिन्न राज्यों के चुनाव नतीजों की वैधता पर भी सवाल उठने वाला है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 नवंबर का इण्डिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार को यथा शीघ्र हटा पायेगा?

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

जीवन का संघर्ष



एक दिन एक व्यक्ति बहुत परेशान लग रहा था। मित्र ने पूछा- क्या बात है? आज इतने परेशान क्यों हो?

उसने कहा- मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूं।

मित्र बोला- तुम्हारी क्या मुसीबत हो सकती है? तुम्हारे दोनों लड़के संपन्न हैं। खूब धन कमा रहे हैं। तुम्हें किस बात की कमी है?

तुम ठीक कहते हो। लड़के संपन्न हैं, पर मेरी मुसीबत उनके कारण ही है। ऐसा क्या हुआ, जो मुसीबत आ गई? मुसीबत बहुत बड़ी है। मैंने लड़कों को पढ़ाया। एक डॉक्टर बन गया और एक वकील। उनका यह व्यवसाय ही मुसीबत का कारण है।

उनके व्यवसाय से आपकी मुसीबत का लेना-देना क्या है?

हुआ यह कि एक एक्सीडेंट में मेरे पैर में चोट लग गई, पैर में घाव हो गया। जो डॉक्टर है, वह कह रहा है, पिताजी! घाव को जल्दी ठीक कर लें अन्यथा इसमें रस्सी पड़ जाएगी। हो सकता है फिर पैर काटने के सिवाय कोई विकल्प न रहे। यह तो अच्छी बात है। इसमें मुसीबत का प्रश्न ही कहां है? लेकिन जो वकील है, वह कह रहा है पिताजी! अभी घाव को ठीक नहीं करना है। इसे बढ़ने दें। जब घाव गहरा हो जाएगा, तब मैं दावा करूंगा और पूरा हर्जाना वसूल करूंगा। यही मेरी मुसीबत है। यह जीवन का संघर्ष है, टकराहट है। व्यक्ति दोनों ओर से खिंचा जा रहा है। एक लड़का कहता ठीक कर लें और एक लड़का कह रहा -घाव को और गहरा होने दें। यह जीवन का विचित्र संघर्ष है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जी रहा है और संघर्षो को झेल रहा है।

संसद में सेंसरशिप या लोकतंत्र? राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती

(लेखक- सनत जैन)

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं है, बल्कि वह मंच है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र दो पैरों पर चलता है, एक सत्ता पक्ष का होता है और एक विपक्ष का। जब संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर न मिले, उसके प्रस्तावों पर चर्चा न हो, सांसदों के भाषणों को कार्यवाही से हटा दिया जाए, बोलने से पहले ही प्रमाण तथा ऑथेंटिकेशन के नाम पर आपत्तियां लगने लगें, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? पिछले एक दशक में संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की जगह टकराव बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आई हैं। विपक्ष का आरोप है, लोकसभा और राज्यसभा में उसके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जाती है। विपक्षी सांसद जब किसी गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए खड़े होते हैं, तब नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देकर उन्हें रोका जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति सर्वसम्मति से चुना जाता है। वह किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन विपक्ष और आप को लगता है कि आसंदी सत्ता पक्ष के दबाव में निर्णय करती है। यदि कोई सदस्य अपनी बात कह भी देता है, तो जो अंश सरकार को पसंद नहीं होते हैं, उसके अंश कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं। विपक्ष इसे अघोषित संसदीय सेंसरशिप के रूप में देख रहा है। विपक्ष का सवाल है, जब सांसदों और राजनीतिक दलों को यह भी तय करने की स्वतंत्रता नहीं है, वह जनता से जुड़े मुद्दे किस तरह से उठाएं, तब संसद में उनकी भूमिका आखिर क्या रह जाती है?

इसी पृष्ठभूमि में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच पर खुली बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री अपनी पसंद का स्थान और मंच तय कर सकते हैं। अपनी पसंद का जज रख सकते हैं। अमेरिकी व्यापार समझौता, अडानी प्रकरण, देश की अर्थव्यवस्था, एसआईआर, घुसपैठियों, चुनाव आयोग, विपक्ष पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने की साजिश के आरोप, इन सभी विषयों पर आमने-सामने चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा, प्रधानमंत्री चाहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को इस बहस में जज के रूप में शामिल कर सकते हैं। राहुल गांधी का तर्क है, जनता को यह जानने का अधिकार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अपने-अपने आरोपों के समर्थन में कौन से तथ्य और प्रमाण हैं। वह सार्वजनिक रूप से जनता को बताएं। इस चुनौती के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर एसआईआर, ईवीएम और घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की प्रस्तावित सार्वजनिक बहस को नकली संसद की संज्ञा देते हुए उन पर विदेशी मदद से सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। इस तरह दोनों पक्षों ने बहस की चुनौती तो दी है, लेकिन बहस का मंच और मुद्दे अलग-अलग रखे हैं। सत्ता पक्ष ने विशेष सत्र बुलाकर बहस करने की मांग को स्वीकार किया है, वहीं विपक्ष खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे रहा है। सवाल यह है, जब विपक्ष संसद के भीतर चर्चा के अवसर सीमित होने की शिकायत कर रहा है, तब संसद में विशेष सत्र बुलाने की पेशकश उसकी मूल आपत्ति का समाधान कैसे करेगी? संसद में बहस के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति, निष्पक्ष संचालन और पर्याप्त समय जरूरी है। केवल बहस की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। जिन मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। जिन आरोपों को विपक्ष लगा रहा है, उनके प्रमाण भी सार्वजनिक होने चाहिए। संसद के विशेष सत्र में यह मौका विपक्ष को नहीं मिलेगा इतना तय है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों में किए जा रहे बदलाव, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईवीएम की विश्वसनीयता, विदेशी हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था और बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़े सवाल, ऐसे विषय हैं, जिनका जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, तथ्यों और प्रमाणों से मिलना चाहिए। सरकार का यह दायित्व है, वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी है, वह अपने आरोपों को प्रमाणों के साथ जनता के सामने रखे। किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठने पर उसका समाधान पारदर्शिता और संस्थागत प्रमाणों की जवाबदेही से ही संभव है।

अमेरिका सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों में सार्वजनिक बहस और मीडिया के सामने सवाल-जवाब की परंपरा कई दशकों पुरानी है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी हो गई है, आज का सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तब इसने उस समय की सत्ता पर बड़े-बड़े आरोप लगाए थे। 12 साल से अधिक समय सत्ता में रहने के बाद किसी भी आरोप को प्रमाणित यह सरकार नहीं कर सकी है। ऐसी स्थिति पर आरोपों की राजनीति पर तभी विराम लग सकता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने की आजादी हो। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में बराबर के पद हैं। शीर्ष पद पर बैठे दोनों निर्वाचित नेता महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकें, इसके लिए बहस का मंच निष्पक्ष हो।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अनिश्चितता के दौर में लार्जकैप पर बढ़ा भरोसा

विशेषज्ञ बोले, अगले 6-18 महीने बेहतर रिटर्न की उम्मीद

नई दिल्ली ।

साल 2026 में शेयर बाजार का रुख बदल गया है। अब तक बाजार की तेजी में आगे रहे मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में लार्जकैप शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं। 11 सितंबर के बाद यह रुझान स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर से 2 नवंबर के बीच निफ्टी 50 में जहां 0.5 फीसदी की मामूली गिरावट आई, वहीं निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 7 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 6.6 फीसदी लुढ़क गया। यह बदलाव दर्शाता है कि निवेशक अब मजबूत कारोबार, आसान तरलता और स्थिर कमाई वाली बड़ी कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 6 से 18 महीनों में लार्जकैप शेयर जोखिम के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अमेरिका चुनाव, कंपनियों की कमाई और वैश्विक तनाव जैसी कई अनिश्चितताएं बाजार के सामने हैं। ऐसे माहौल में लार्जकैप शेयर निवेशकों को अधिक स्थिरता दे रहे हैं। मजबूत कारोबार, बैलेंस शीट और स्थिर कमाई वाली बड़ी कंपनियां आकर्षक बनी हुई हैं। एफआईआई की लगातार बिकवाली चुनौती रही है, पर वैश्विक भरोसा बढ़ने पर निफ्टी 50 कंपनियां, प्राइवेट बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता सबसे पहले लाभ उठा सकते हैं। निवेशक अब कम समय में ऊंचे रिटर्न से ज्यादा, बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना करने की लार्जकैप की क्षमता को अहमियत दे रहे हैं।

यूपी सरकार दिवाली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को बांटेगी निःशुल्क गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, लाभार्थियों के खातों में पहुंची सब्सिडी

लखनऊ ।

दीपावली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन का सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल लाखों परिवारों के लिए त्योहार को और भी रोशन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ के लोकभवन से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत, उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी के खाते में कुल 971 रुपये (राज्य सरकार से 653 रुपये और केंद्र सरकार से 318 रुपये) की सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जा रही है। यह सुविधा लाभार्थियों को साल में दो बार प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें ईंधन के खर्च से राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत, जनपद एटा में भी जिलाधिकारी एम अरुन्मोली की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक वितरित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की, जो स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर है। जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता के अनुसार, एटा में 1,74,934 उज्ज्वला लाभार्थियों को इस दीपावली पर लाभ मिल रहा है। सरकार की यह पहल स्वच्छ ईंधन उपलब्धता और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

घर बैठे मनाएं, जेप्टो और ब्लिं किट पर मिलेगा सारा सामान

नई दिल्ली ।

आस्था और लोकपर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी।

इस दौरान बाजारों में लगने वाली भारी भीड़ और खरीदारी की जद्दोजहद से बचने के लिए, जेप्टो और ब्लिं किट जैसे ऑनलाइन क्रिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं।

अब आप घर बैठे ही छठ पूजा से जुड़ा लगभग सभी आवश्यक सामान आसानी से मंगवा सकते हैं।

इन प्लेटफॉर्म्स पर कपूर, देसी घी के दीये, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप, रोली, मौली और चावल जैसी पारंपरिक पूजा सामग्री आसानी से मिल रही है। इसके साथ ही, पूजा की थाली, लाल-पीले वस्त्र और ठेकुआ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध है। व्रतियों के लिए विभिन्न प्रकार के ताजे फल जैसे केला, सेब, अमरूद और अनार भी घर बैठे मंगाए जा सकते हैं। इन क्रिक कॉमर्स सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका सामान अक्सर मिनटों के भीतर ही घर तक पहुंच जाता है, जिससे समय की बचत होती है और बाजार जाने की परेशानी खत्म हो जाती है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 383, निफ्टी 149 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुए। बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। आज कारोबार के दौरान बीईएल, टाइटन, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व के शेयरों में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस के शेयर गिरे। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 383.55 अंकों की बढ़त के साथ ही 77,301.40 अंकों पर बंद हुआ। जबकि 50 शेयरो वाला , एनएसई निफ्टी 149.75 अंकों से उछलकर 23,960.60 अंकों पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ ही ऊपर आये जबकि शेष 9 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ही नीचे आये। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 की 50 में से 36 कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए और बाकी की 14 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ नीचे आये। सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल सरकारी डिफेंस कंपनी बीईएल के शेयर आज सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए। जबकिटीसीएस के शेयर आज सबसे ज्यादा टूटे।



सेंसेक्स के अन्य शेयरों में आज टाइटन, इंडिगो 2, बजाज फाइनेंस, आईटीसी , अडाणी पोर्ट्स तेजी के साथ बंद हुए जबकि आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल के शेयरों में बदलाव नहीं आया। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की धीमी शुरुआत हुई। सेंसेक्स 65 अंक टूटकर 76,853.11 के स्तर पर लगभग सपाट स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 50 भी 0.28 फीसदी की गिरावट के साथ 23742.25 के स्तर पर शुरु हुआ।

पीएनबी और केनरा बैंक ने बदली एफडी ब्याज दरें

- वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा विशेष लाभ

नई दिल्ली ।

यदि आप सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।

देश के प्रमुख सरकारी बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और केनरा बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को आकर्षक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। केनरा बैंक ने 2 नवंबर से अपनी एफडी दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। बैंक की 555 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को अब 6.75 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं, 444 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.65 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.15 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से, केनरा बैंक की दरें अधिक लुभावनी हैं। दूसरी ओर, पीएनबी ने 1 नवंबर से नई दरें लागू की हैं। बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को अधिकतम 6.60 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 फीसदी ब्याज मिलेगा। 666 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों के लिए 6.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.00 फीसदी की दर निर्धारित की गई है। ये दरें 3 करोड़ रुपए से कम की घरेलू टर्म डिपॉजिट पर लागू हैं। स्पष्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों को दोनों बैंकों में एफडी पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे उनके लिए यह निवेश और भी आकर्षक हो जाता है।

सेवा क्षेत्र में जोरदार बढ़ोतरी, 4 माह का उच्चतम स्तर

अक्टूबर में एचएसबीसी पीएमआई 55.2 से बढ़कर 55.8 पर पहुंचा

नई दिल्ली ।

भारत के सेवा क्षेत्र ने अक्टूबर में चार महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई सूचकांक सितंबर के 55.2 से बढ़कर 55.8 पर पहुंच गया, जो मांग में मजबूती और नए ऑर्डर की बंपर आवक को दर्शाता है। अच्छी खबर यह भी है कि लागत का दबाव कम हुआ है, जिससे कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सर्वेक्षण के अनुसार, 50 से ऊपर का अंक विस्तार का सूचक होता है। कंपनियों ने नए ग्राहकों, अनुकूल मांग परिस्थितियों और सफल विज्ञापन अभियानों के दम पर नए ऑर्डर में जोरदार वृद्धि दर्ज की। एचएसबीसी की एक अर्थशास्त्री ने पुष्टि की कि कुल मांग काफी मजबूत बनी रही, जिससे कारोबारी स्थितियों में सतर्कता के साथ सुधार हुआ। हालांकि, कुछ मोर्चों पर सतर्कता भी दिखी। कंपनियों ने भविष्य की संभावनाओं को लेकर आशावादी रहने के बावजूद चार महीने में सबसे कम कर्मचारियों की भर्ती की, जो रोजगार वृद्धि की धीमी रफ्तार को दर्शाता है। नए निर्यात ऑर्डर की वृद्धि लगभग चार साल में सबसे कमजोर रही। अच्छी बात यह है कि कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई, जिससे महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिली।

भारत में 2027 से विमान ईंधन में एसएएफ का उपयोग अनिवार्य होगा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की ड्राफ्ट एसएएफ पॉलिसी, 2026

नई दिल्ली ।

भारत सरकार हवाई यात्रा को पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट एसएएफ पॉलिसी, 2026 के तहत विमानों के ईंधन एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) में एसएएफ (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इस नई नीति के लागू होने पर, जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कम से कम एक फीसदी का उपयोग करना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह नीति अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जनवरी 2027 से एक फीसदी एसएएफ के उपयोग को अनिवार्य करेगी और 2040 तक इस लक्ष्य को 20 फीसदी तक बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। एसएएफ पारंपरिक विमान ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जिसे फसल, जैविक कचरे और अन्य टिकाऊ स्रोतों से तैयार किया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई यात्रा के कार्बन पदचिह्न को कम करना है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसएएफ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे। ड्राफ्ट नीति में केवल एसएएफ मिश्रण के लक्ष्य ही नहीं, बल्कि इनके सख्त अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित ब्लेंडिंग जरूरत को पूरा न करने वाली एयरलाइंस और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी प्रस्तावित है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी वार्षिक एटीएफ जरूरतों का कम से कम 90 फीसदी भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से पूरा करेंगी, जिसका लक्ष्य इकोनॉमिक टैंकरिंग को रोकना है। हवाई अड्डों को एसएएफ के भंडारण, रखरखाव और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसएएफ के उपयोग से एयरलाइंस की ईंधन लागत पर असर पड़ सकता है, खासकर यदि एसएएफ पारंपरिक एटीएफ से महंगा होता है, तो हवाई टिकटों की कीमतों में वृद्धि संभव है। हालांकि, फिलहाल हवाई टिकटों के महंगा होने की कोई तत्काल संभावना नहीं जताई गई है। यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल हवाई यात्रा को बढ़ावा देने वाले देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा।



एस्सार पावर आंध्र में 4500 करोड़ से लगाएगा हाइब्रिड ऊर्जा प्लांट

निवेश, सौर, पवन और बैटरी स्टोरेज से मिलेगी विश्वसनीय ऊर्जा

नई दिल्ली ।

एस्सार पावर आंध्र प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 4,500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने जा रही है। कंपनी ने अपनी नवीकरणीय इकाई, एस्सार रिन्यूएबल्स लिमिटेड (ईआरएल) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी लिमिटेड के साथ 300 मेगावाट की बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद यह परियोजना धरातल पर उतरेगी। यह निवेश एस्सार पावर के भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अत्याधुनिक परियोजना सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का उपयोग करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय और मांग के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सकने वाली नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

यह समझौता नवीकरणीय, तापीय और गैस आधारित बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में करीब पांच गीगावाट का विविध ऊर्जा कारोबार तैयार करने की एस्सार पावर की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

एस्सार पावर के एक वे रिठ अे धिकारी ने कहा कि यह समझौता सौर, पवन और बैटरी भंडारण के क्षेत्रों में कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को मजबूत करेगा। उन्होंने इसे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार खड़ा करने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।

यह परियोजना कंपनी के पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार एक टिकाऊ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायक होगी।

एमके सन्स फाइन ज्वेल्स का शेयर छह प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

एमके सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड के शेयरों ने बुधवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की।

कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य 162 रुपये से करीब छह प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ, जिससे निवेशकों को लिस्टिंग पर ही फायदा हुआ। बीएसई पर शेयर 5.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 171.60 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि एनएसई में यह 5.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 171 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 924.86 करोड़ रुपये रहा। पिछले सप्ताह, कंपनी के 275 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के अंतिम दिन तक 5.09 गुना अभिदान मिला था। कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग महाराष्ट्र में एक नया शोरूम खोलने, गुजरात में मौजूदा शोरूम के विस्तार, कुछ कर्जों का भुगतान करने और सामान्य कारोबारी उद्देश्यों के लिए करेगी। वर्ष 2012 में स्थापित एमके सन्स फाइन ज्वेल्स लिमिटेड आभूषणों के डिजाइन, विनिर्माण और खुदरा बिक्री के कारोबार में एक जानी-मानी कंपनी है।

दिवाली पर महंगाई की मार,अमूल घी-बटर महंगा

1 किलो घी 50 और 500 ग्राम बटर 15 रुपए महंगा

नई दिल्ली ।

दिवाली नजदीक आते ही उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। अमूल ने अपने घी और बटर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे त्योहारों पर पकवान बनाने का बजट प्रभावित होगा। अमूल के नए दामों के अनुसार 1 किलो घी कार्टून अब 630 की जगह 680 रुपये में, यानी 50 रुपये महंगा मिलेगा। 500 ग्राम बटर पैक 310 से बढ़कर 325 रुपये का हो गया है। 500 ग्राम प्योर घी पाउच 345 रुपये में, जबकि 100 ग्राम बटर पैक 63 से 66 रुपये में मिलेगा। कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गाय का घी 740 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कीमतों में इस वृद्धि की मुख्य वजह घी की बढ़ती मांग और आपूर्ति में कमी है। त्योहारों पर सालभर की कुल घी खपत का करीब 45 प्रतिशत इस्तेमाल होता है। मिलावटी घी पर सख्ती के बाद ग्राहकों का रुझान ब्रांडेड घी की ओर बढ़ा, जिससे मांग और बढ़ी। गुजरात के अहमदाबाद व वडोदरा में अमूल घी, खासकर गाय के घी की उपलब्धता में भी कमी देखी जा रही है। सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कमी के बाद मिली राहत अब इस नई बढ़ोतरी से खत्म हो गई है। ऐसे में दिवाली के लिए मिठाइयां और पकवान बनाने वालों की जेब पर यह बढ़ोतरी सीधा असर डालेगी।



आरबीआई ने सेवा निर्यात-आयात के नियमों में ढील दी, फ्रीलांसरों को राहत

छोटे ट्रांजेक्शन और डिजिटल सेवाओं के लिए ईडीएफ की बाध्यता खत्म

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े विदेशी मुद्रा नियमों में महत्वपूर्ण ढील दी है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स से कमाई करने वाले फ्रीलांसरों, कंपनियों और आयातकों को बड़ी राहत मिली है। इन बदलावों का उद्देश्य छोटे ट्रांजेक्शन और सेवा भुगतानों की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे कागजी कार्रवाई और लगने वाले समय में कमी आएगी। नए नियमों के तहत भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अब विदेश में सेवा देने के बदले भुगतान मिलने पर अलग से एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फार्म (ईडीएफ) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपने बैंक को भुगतान खाते में जमा करने के लिए आवश्यक जानकारी देनी होगी। यह कदम विशेष रूप से डिजिटल सेवाओं और फ्रीलांसिंग के बढ़ते क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जहां अक्सर छोटे भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं। जो निर्यातक भारत में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसे निर्यातकों के लिए विदेश से आने वाली सर्विस पेमेंट 10 लाख रुपये तक होने पर सिर्फ बैंक को जरूरी जानकारी देनी होगी; इससे अधिक राशि पर पहले के डिक्लेरेशन की शर्तें ही लागू होंगी। आरबीआई ने सर्विस इंपोर्ट के मामले में भी रिपोर्टिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब बैंकों को इम्पोर्ट डाटा प्रोसे सिंग एंड मो निटे रिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) में सर्विस इंपोर्ट की जानकारी तभी दर्ज करनी होगी, जब सेवा खरीदने वाला भारत का निवासी न हो और इनवॉयस 10 लाख रुपये से अधिक हो। इन बदलावों से विदेशी व्यापार से जुड़े लेन-देन की प्रक्रिया में लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी, जिससे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका और उसकी सीमाएं

सीमित सलाह दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, पूरी वित्तीय योजना के लिए पंजीकृत सलाहकार चुनें

नई दिल्ली ।

म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और पूर्ण वित्तीय सलाहकार की भूमिकाओं को लेकर निवेशकों में अक्सर भ्रम रहता है। इसे दूर करने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) ने हाल ही में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद निवेशकों को सही जानकारी देना और उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं के लिए सही व्यक्ति चुनने में मदद करना है, खासकर सोशल मीडिया पर सलाह की बढ़ती भरमार के बीच। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का प्राथमिक काम निवेशकों को उनकी जरूरतों, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार उपयुक्त म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने में मदद करना है। वह केवाईसी अपडेट करने और बैंक खाते बदलने जैसे प्रशासनिक कार्यों में भी सहायता कर सकता है। हालांकि,एएमएफआई ने स्पष्ट किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह केवल म्यूचुअल फंड तक सीमित है, यह किसी निवेशक की पूरी वित्तीय योजना का हिस्सा नहीं है। व्यापक वित्तीय योजना (जिसमें घर खर्च, बच्चों की शिक्षा, बीमा और रिटायरमेंट जैसे कई पहलू शामिल हैं) के लिए आपको सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से संपर्क करना जरूरी है। एएमएफआई ने सोशल मीडिया पर म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। वे बिना निवेशक की व्यक्तिगत जरूरत और जोखिम को समझे किसी खास स्कीम की सीधी सिफारिश नहीं कर सकते और न ही भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाकर दावा कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें अपनी पहचान और एएमएफआई पंजीकरण नंबर (एआरएन) स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है।



एससी ने राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा

सात-न्यायाधीशों की पीठ ने 1974 के संविधान पीठ के फैसले को प्रभावी बताया

नई दिल्ली ।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के पास बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर या अधिभार लगाने का अधिकार अब भी वैध है। न्यायालय ने 1974 के संविधान पीठ के फैसले को प्रभावी बताया और कहा कि जीएसटी लागू होने से करीब 27 साल पहले भेजे गए कानूनी सवाल पर अब निर्णय देना अनावश्यक है, क्योंकि यह अकादमिक हो चुका है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि करीब 27 साल पुराने कानूनी सवाल पर अब निर्णय की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने इसका कारण बताते हुए कहा कि चुनौतीग्रस्त वैधानिक प्रावधानों में बदलाव और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के चलते यह सवाल अब अकादमिक हो चुका है व इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एस. कोदार बनाम केरल राज्य (1974) मामले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला अब भी प्रभावी है। उस फैसले में अधिभार को बिक्री कर की दर में वृद्धि माना गया था, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 (वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर) के तहत आता है, न कि आय पर कर (सूची-1 की प्रविष्टि 82) के तहत। यह संदर्भ ओडिशा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5ए को चुनौती दिए जाने से उठा था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रोज की भागदौड़ छोड़िए और जाइए घूमने

अगर आप लंबे समय से घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन काम की वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस वीकेंड घूमने का प्लान बना सकते हैं। ऐसे में आप वीकेंड पर न सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं, बल्कि आप अपने परिवार के साथ नई जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको वीकेंड ट्रिप पर घूमने के लिए यहां कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी फैमिली, दोस्तों और पार्टनर के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं।

मथुरा-वृंदावन

आप इस वीकेंड कान्हा की नगरी मथुरा-वृंदावन जा सकते हैं। आप मथुरा में कृष्ण कारागार और फिर अगले दिन वृंदावन और बरसाना घूम सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर प्रेम मंदिर, निधिवन, बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर घूमने जा सकते हैं।

अमृतसर

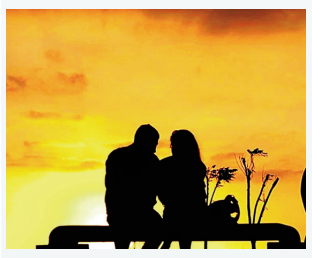
आप वीकेंड पर फैमिली के साथ जलियांवाला बाग घूमने जा सकते हैं। यहां पर पहुंचने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा 12 किमी दूर अमृतसर एयरपोर्ट है। वहीं अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन से करीब 2 किमी दूर जलियांवाला बाग है। जहां पर आप रिक्शा, ऑटो या फिर पैदल भी जा सकते हैं। जलियांवाला बाग से स्वर्ण मंदिर की दूरी 500 किमी है।

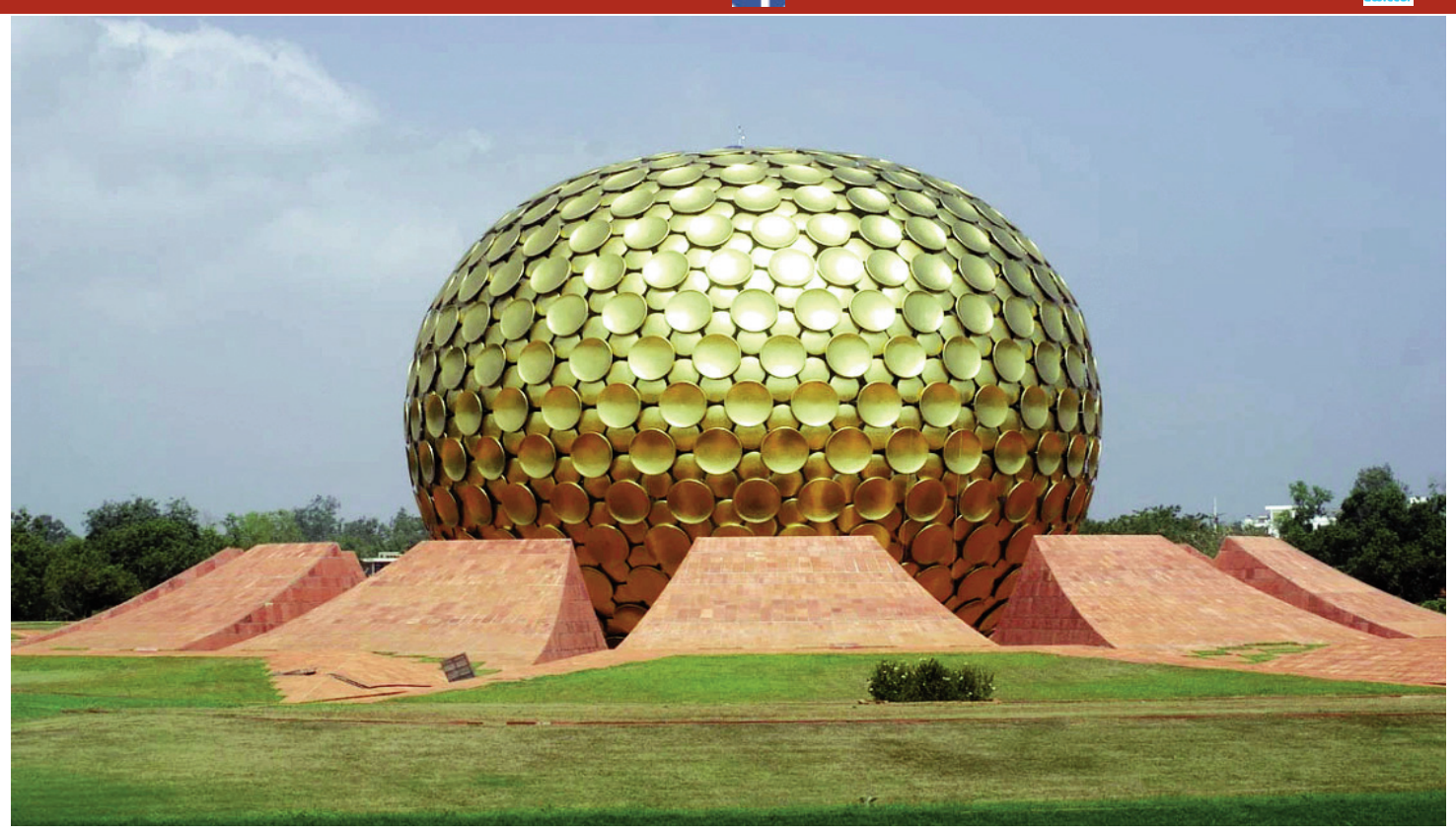
ऋषिकेश

उत्तराखंड का ऋषिकेश वीकेंड ट्रिप के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहां पर आपको आध्यात्मिक और एडवेंचर अनुभव का मेल मिलेगा। आप गंगा किनारे शांत माहौल में सुकून के पल बिता सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं।

उदयपुर

बता दें कि राजस्थान का उदयपुर खूबसूरत झीलों का शहर है। यह रोमांटिक और फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे तो उदयपुर में कई घूमने वाली जगहे हैं, जैसे आप पिछोला झील, सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और जगदीश मंदिर आदि एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में यहां के लजीज व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं।





भारत में सोलो ट्रिप के लिए बेहद शानदार जगहें

घुमक्कड़ लोग घूमने के इतने शौकीन होते हैं कि कई बार वे अकेले ही निकल जाते हैं। ऐसे में सोलो ट्रिप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अकेले यात्रा करना खुद के साथ समय बिताने, नए लोगों से मिलने और अनोखे अनुभवों का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। जब बाता आती है महिलाओं के लिए, अब भारत भर में कई ऐसे स्थान हैं जो सुंदर और सुरक्षित दोनों हैं। इन स्थानों पर महिलाएं जरुर जाएं।

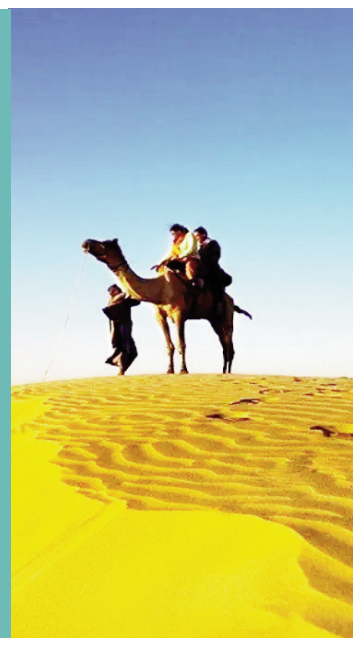
ऋषिकेश, उत्तराखंड



सोलो ट्रिप के लिए महिलाओं के लिए ऋषिकेश सबसे बेस्ट जगह है। अपनी आध्यात्मिकता, योग केंद्रों और गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है ऋषिकेश। यहां पर आपको शांत वातावरण के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक एडवेंचर एक्टिवी का आनंद भी ले सकते हैं। यहां रहने की व्यवस्था बजट-अनुकूल हॉस्टल से लेकर होटल तक उपलब्ध है। महिलाएं सुरक्षित रूप से गंगा के तटों की सैर कर सकती हैं और ध्यान व योग का आनंद ले सकती हैं।

जैसलमेर, राजस्थान

सोलो ट्रिप को खास बनाने के लिए आप राजस्थान के जैसलमेर में जरुर जाएं। गोल्डन सिटी जैसलमेर में रेगिस्तान देखना एक जादुई जगह जैसा लगता है। यहां पर आपको ऐतिहासिक किला, हवेलियां और थार रेगिस्तान में ऊंट सफ़ारी वाकई एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। स्थानीय संस्कृति, टेस्टी राजस्थानी व्यंजन और गर्मजोशी भरा आतिथ्य हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिलती है ऐसे में महिलाएं यहां पर आराम से अकेले भी घूम सकती हैं।



खूबसूरत मठ और आरामदायक कैफे यादगार सोलो ट्रिप का अनुभव प्रदान करेंगे। यहां पर आ ट्रेकिंग और प्रकृति की सैर कर सकते हैं। धर्मशाला के स्थानीय लोग मिलनसार और सुरक्षित वातावरण के कारण महिलाएं अंधेरे के बाद भी आजादी से घूम सकती हैं।

पुडुचेरी

अपनी फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला, समुद्र तटों और कलरफुल गलियों के लिए प्रसिद्ध है पुडुचेरी। सोलो ट्रिप करने वाली महिलाओं के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। यहां के कैफ़े, ऑरोविले आश्रम और योग केंद्र एक ताजा और आरामदायक अनुभव प्रदान करेगा। शांत और सुरक्षित वातावरण में, महिलाएं पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपनी यात्रा का आनंद ले सकती हैं।

अलेप्पी, केरल

अगर आपको पानी के किनारे समय बिताना पसंद है, तो केरल का अलेप्पी आपके लिए एकदम सही जगह है। शांत बैकवाटर्स के किनारे हाउसबोट की सवारी और हरे-भरे नारियल के बागों के बीच एक सुकून भरा माहौल है। अकेले घूमने वाले लोग इस शांत वातावरण में सुकून के पल बिता सकते हैं और केरल के असली व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां का स्थानीय पर्यटन उद्योग महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत जोर देता है।

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला और पास का मैक्लोडगंज माउंटेन लवर के लिए एकदम सही जगह है। यहां पर आपको तिब्बती संस्कृति,



मनाली के पास 100 किमी में छुपे ये 3 हिल स्टेशन, जहां मिलेगा अद्भुत सुकून और शांति



जब भी लोग पहाड़ी जगहों पर घूमने जाने का प्लान करते हैं, तो वह आसपास की सभी जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं। कई बार लोग ऐसी लोकेशन के बारे में सर्च करते हैं, जो आपकी लोकेशन के पास भी हो और साथ ही खूबसूरत भी हो। वहीं अपने शहर से दूर घूमने गए लोग हमेशा पूरी प्लानिंग करने के बाद जाते हैं। क्योंकि लंबे ट्रिप पर निकले लोग आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे में अगर आप भी मनाली के आसपास 100 किमी के अंदर अच्छी जगहें ढूंढ रहे हैं, जहां पर जाने में अधिक समय नहीं लगे। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मनाली से 100 किमी की दूरी पर स्थित कुछ हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं।

मणिकर्ण

बता दें कि मनाली से मणिकर्ण की दूरी करीब 100 किमी के अंदर है। आप यहां पर 2:30 से 03:00 घंटे में पहुंच जाएंगे। मनाली घूमने गए लोगों को आसपास की जगहों को कवर करना चाहिए। इससे न तो ज्यादा खर्च आएगा और न ही आपको लोकेशन तक पहुंचने पर अधिक समय लगेगा। मनाली से मणिकर्ण की दूरी करीब 79 किमी दूर है। आप मणिकर्ण पहुंचकर कसोल भी जा सकते हैं। कसोल और मणिकर्ण की बीच की दूरी करीब 20 मिनट की है।

कसोल

मनाली घूमने वाले लोगों को कसोल भी आना चाहिए। क्योंकि यह जगह मनाली से 100 किमी से भी कम दूरी पर स्थित है। अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। मनाली से कसोल की दूरी करीब 75 किमी है। बता दें कि कसोल और कसोली 2 अलग-अलग जगहें हैं। जिसमें कसोल ऊंचाई पर स्थित है और यह एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपनी सुकून और शांति के लिए जाना जाता है।

रोहतांग पास

मनाली के पास सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह रोहतांग पास है। मनाली घूमने जाने वाले लोग रोहतांग पास घूमने जरूर जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मनाली से अधिक दूर नहीं है। इसलिए लोगों को यहां पर पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मनाली से रोहतांग पास की दूरी करीब 50 किमी है। आप यहां पर 2 घंटे में आसानी से पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचने में अधिक खर्च नहीं आने वाला है। ऐसे में अगर आप भी मनाली घूमने जा रहे हैं, तो यहां आसपास मौजूद इन हिल स्टेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

आ रही हैं सर्दियां... टॉप 5 डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं घूमने, ठंड के मौसम में चमक उठती हैं ये जगहें

अगर आपने अपने परिवार के साथ लंबे समय से कोई ट्रिप प्लान नहीं किया है, तो आप भारत की उन जगहों पर जा सकते हैं, जहां ठंड के मौसम में मजा दो गुना हो जाता है। यही नहीं ये जगह ज्यादा महंगी भी नहीं है।



फेस्टिव सीजन और ठंड दोनों ही आ रहे हैं, ऐसे में कई बच्चों को विंटर वेकेशन भी मिलेगी, तो घूमने का प्लान बनाया जा सकता है। आपको बता दें, भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां ठंड में घूमने का मजा कुछ और ही होता है। अगर आप भी लंबे समय से कहीं नहीं घूमें हैं, तो आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ एक प्यारा से ट्रिप कर सकते हैं। बजट के मामले में ये जगहें ज्यादा महंगी नहीं है। आइए जानते हैं, इन डेस्टिनेशन के बारे में।

शिमला, हिमाचल प्रदेश

शिमला एक फेमस हिल स्टेशन है जहां अक्टूबर महीने से ही सर्दी का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इस समय के दौरान, टूरिस्ट शिमला के मॉल रोड पर इत्मीनान से सैर करने का आनंद ले सकते हैं, यही नहीं यहां के फेमस क्राइस्ट चर्च ; द स्केंडल पॉइंट घूम सकते हैं। सर्दियों के मौसम में शिमला आपको सफेद चादर से ढका हुआ मिलेगा। शिमला में घूमने की काफी जगहें हैं। कुफरी जाकर आप अपने परिवार से साथ कई विंटर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

दिल्ली, चंडीगढ़, को लोग सर्दी हो या गर्मी मनाली को हमेशा टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट में रखते हैं। सर्दियों में मनाली देखने लायक है। यहां की कड़कड़ाती ठंड और मॉल रोड की गर्मागर्म चाय के सामने हर सुकून फेल है।यहां आप हिडिम्बा मंदिर, वशिष्ठ कुण्ड,मणिकरण, रोहतांग पास, ओल्ड मनाली समेत कई टूरिस्ट पॉइंट देख सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी ये जगह बेस्ट है। यहां



ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प, बर्तन, घर की सजावट की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसी के साथ यहां आप दोनों पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं।

दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल

दार्जिलिंग एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहां आपको किसी भी मौसम में जाओ ये जगह आपको कभी निराश नहीं करेगी, अगर आप सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं, तो खिलती हुई धूप जब हरे-भरे चाय बागानों पर पड़ती है, तो नजारा देखने लायक होता है। यही नहीं, यहां पर आकर आप टॉय ट्रेन, टाइगर हिल्स, तासिया लूप, जापानी मंदिर और रॉक गार्डन जैसे प्लेस देख सकेंगे।इसी के साथ आप यहां सबसे बेस्ट सनराइज का मजा ले सकते हैं। बता दें, अगर आप बच्चों के साथ यहां ट्रैवल कर रहे हैं, तो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन का सफर करवाना न भूलें। देशभर से टूरिस्ट टॉय ट्रेन का सफर का मजा लेने आते हैं।

औली, उत्तराखंड

उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन है, वहीं टूरिस्ट औली हिल स्टेशन आना काफी पसंद करते हैं। बता दें, अक्टूबर- नवंबर में यहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए ये जगह बेस्ट है। स्कीइंग और बर्फ से संबंधित एक्टिविटी के लिए औली जाना बेस्ट ऑप्शन रहेगा।

काजा

स्पीति घाटी में स्थित काजा एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, जहां ज्यादातर टूरिस्ट सर्दियों में आना पसंद करते हैं। जैसे- जैसे यहां तापमान गिरता जाता है, पूरा काजा शहर बर्फ की खूबसूरत चादर से ढक जाता है। इसी के साथ यहां आकर आप मोनेस्ट्री और किब्बर जैसे प्राचीन मठों पर घूम सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों पर जोर, रुबियो को कमान

वेनेजुएला , एजेंसी। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोमवार को अपने वेनेजुएला के समकक्ष ओलिवर ब्लैंको से मुलाकात की। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। अगले साल चुनाव संभव हैं। दो सप्ताह पहले ही वेनेजुएला ने 2027 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक योजना पर सहमति दी थी। रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस प्रक्रिया का बारीकी से पालन करेगा। इसका लक्ष्य एक स्थायी चुनाव प्रणाली स्थापित करना है। यह बैठक ट्रंप प्रशासन और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी। रोड्रिगेज ने जनवरी में अमेरिकी सैन्य अभियान में निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद पद संभाला था। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें वह नकारते हैं।

नकाबपोश हमलावरों ने किसान पर जानलेवा हमला किया, पांच गिरफ्तार

डरबन, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में हिंसक डकैती के संबंध में पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 50 वर्षीय किसान डोनावान मार्क्स को गोली मारी गई और उनके कान काट दिए गए थे। ये संदिग्ध 26 से 56 वर्ष के हैं और मंगलवार को आरोपियों को वेंटर्सडॉर्प मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर घर में डकैती, हत्या का प्रयास और अवैध हथियार व गोला-बारूद रखने के आरोप हैं। पुलिस ने पहले दो, फिर रविवार को तीन और संदिग्धों को पोटचेफस्ट्रूम के पास पकड़ा। अधिकारियों ने चार हथियार, कपड़े व आभूषण जब्त किए। हमला 28 अक्तूबर को साइफरफोंटेन के एक खेत पर हुआ। तीन नकाबपोश हमलावरों ने किसान को गोली मारी, चाकू से हमला किया, तीन हथियार चुराए और उसके पिकअप वाहन में भाग गए। किसान अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुआ था और अब ठीक हो रहा है। मोरल रीजेनरेशन मूवमेंट ने कहा कि किसानों पर हमले खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के शोध से पता चला है कि डकैती मुख्य मकसद है, न कि श्वेत किसानों के खिलाफ 'श्वेत नरसंहार' जैसा कोई संगठित अभियान।

वोटिंग से कुछ घंटे पहले अमेरिका का ईरान पर हमला :केश्म द्वीप पर 5 धमाके



तेहरान, एजेंसी। अमेरिका में मंगलवार को मिडटर्म चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले सोमवार को ईरान के केश्म द्वीप पर कम से कम पांच जोरदार धमाके हुए। कुछ दूर पर बंदर लेंगेह शहर में भी विस्फोट की खबर है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि यह हमला अमेरिका ने किया है। हालांकि, ईरानी मीडिया ने इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की पुष्टि नहीं की है। उसने अमेरिका के दो एमक्यूएम-170 जासूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। केश्म द्वीप करीब 1,445 वर्ग किलोमीटर में फैला, ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कभी फ्री-ट्रेड जोन और टूरिस्ट स्पॉट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक बड़े सैन्य ठिकाने में बदल चुका है। होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर मौजूद यह द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अमेरिका इसे कई वजहों से बड़ा सैन्य खतरा मानता है। अंडरग्राउंड सैन्य नेटवर्क: रिपोर्ट्स के मुताबिक, केश्म द्वीप के नीचे सुरंगों और नमक की गुफाओं का बड़ा नेटवर्क है। यहां ईरान ने तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपाकर रखी हैं। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए अहम: द्वीप के अंदर ईरान ने ऐसे सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जिनका मकसद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखना है। माना जाता है कि यहां से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोकी या सीमित की जा सकती है।

एफबीआई ने उत्तर कोरिया पर लगाया क्रिप्टो चोरी का आरोप, भड़की किम जोंग उन की बहन, बताया 'राजनीतिक साजिश'

सोल , एजेंसी। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की उस जांच के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज 'बायनैंस' से हुई भारी क्रिप्टोकरेंसी चोरी के लिए प्योंगयांग को जिम्मेदार ठहराया गया था। उत्तर कोरिया ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश और भड़काऊ कृत्य करार दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के शनिवार के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि 'बायनैंस' के जरिए 6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी के लिए उत्तर कोरियाई शासन जिम्मेदार है। एफबीआई ने इस चोरी का संबंध उत्तर कोरिया के एक हैकिंग समूह से जोड़ा है, जिसे वे 'ट्रेडर ट्रेटर' कहते हैं। इस नाम का संबंध पहले भी क्रिप्टोकरेंसी की अन्य चोरियों से जोड़ा जा चुका है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' में प्रकाशित एक बयान में किम ने कहा, 'उत्तर कोरिया (डीपीआरके) को एक 'साइबर अपराधी देश' के रूप में एफबीआई पेश करने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि इस



घटना में उत्तर कोरिया 'समर्थित' एक हैकिंग संगठन शामिल था।' डीपीआरके, उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया' का संक्षिप्त रूप है। बयान में कहा गया, 'यह उत्तर कोरिया के खिलाफ एक गंभीर राजनीतिक साजिश है। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको गुमराह कर रहा है, मानो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले सभी साइबर अपराध हमारे ही किए धरे हों। '

उत्तर कोरिया पर पहले भी साइबर चोरी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उसने हमेशा इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। किम का किसी हैकिंग घटना पर बयान जारी करना काफी दुर्लभ है। किम ने वाशिंगटन के आरोपों को उत्तर कोरिया की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने, उसकी गरिमा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कम करने की एक 'दुर्भावनापूर्ण' कोशिश बताया। साथ ही, उन्होंने इसे साइबर स्पेस में उत्तर कोरिया की संप्रभुता का एक और गंभीर उल्लंघन करार दिया।

आरोप को वापस वाशिंगटन की ओर मोड़ते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले साल जब अमेरिका के मौजूदा प्रशासन ने सत्ता संभाली, तो उसने घोषणा की थी कि वह अवैध रूप से चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लेगा और उसे देश के रणनीतिक भंडार के रूप में इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह देखे कि 'तथाकथित चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी' बरामद होने के बाद किसके पास जाएगी, तो 'उसे इस बात का सुराग मिल सकता है कि इस हैकिंग घटना के पीछे कौन है। 'उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया, वाशिंगटन द्वारा लगातार किए जा रहे उकसावे की हरकतों पर 'करीबी नजर' रख रहा है। किम ने चेतावनी देते हुए कहा, 'अमेरिका के इस बेहद गैरजिम्मेदाराना और शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए, हमें कई पहलुओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है।' दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर कोरिया पर लगे साइबर हैकिंग के आरोपों पर किम का यह पहला बयान है।

अधिकारी ने कहा, 'ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि बायनैंस हैकिंग की घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने किम के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है।' अतीत में ऐसे मामलों पर, उत्तर कोरिया आमतौर पर अपने विदेश मंत्रालय के जरिए बयान जारी करके जवाब देता था। अधिकारी ने आगे कहा कि प्योंगयांग अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर चिंतित है, क्योंकि वह खुद को एक 'सामान्य देश' के रूप में पेश करना चाहता है।

इस बयान को एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद उत्तर कोरिया की साइबर गतिविधियों को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने से रोकना है। साथ ही, इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि वह उस नीति को छोड़ दे, जिसे प्योंगयांग अपने खिलाफ एक 'शत्रुतापूर्ण नीति' मानता है।

मंत्रालय के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस हैकिंग घटना का उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली संभावित शिखर वार्ता पर क्या असर पड़ेगा। शिखर वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप की बार-बार की गई पहलों पर उत्तर कोरिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

इस माह भारत आ सकते हैं नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह

काठमांडो, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इस महीने के आखिर में नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी का नेपाल दौरा बालेंद्र शाह की तैयारी के लिहाज से अहम होगा।

नेपाल और भारत ने सोमवार को एक साथ घोषणा की कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी 4 और 5 नवंबर को काठमांडू का दौरा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी अलग-अलग बयानों में कहा गया कि दो दिवसीय यात्रा के दौरान विक्रम मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'दोनों पक्ष नेपाल-भारत संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया जा सके। मंत्रालय के अनुसार, विक्रम मिसरी नेपाल के वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा, 'भारत और नेपाल के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनमें सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विदेश सचिव की यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाएगी और व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने में मदद करेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शाह की प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा के संभावित एजेंडे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि नेपाल चाहता है कि प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा ठोस परिणाम लेकर आए और उन मुद्दों पर प्रगति हो, जिनमें उसे भारत के सहयोग की जरूरत है। नेपाल अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत से एक बड़े सहायता पैकेज की मांग कर सकता है। इसके अलावा नेपाल सीमा विवाद के समाधान, व्यापार संधि में संशोधन और भारत के रास्ते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अतिरिक्त हवाई प्रवेश बिंदुओं (एयर एंट्री प्वाइंट्स) जैसी मांगों पर भी प्रगति चाहता है। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के सहयोग से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा सकता है। बताया गया है कि नई दिल्ली ने पहले मई के दूसरे सप्ताह में विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने की योजना बनाई थी, ताकि प्रधानमंत्री शाह के नेतृत्व में बनी नई सरकार के साथ बातचीत की जा सके।

यूक्रेन में रूस का कहर: राहत केंद्र और शेल्टर पर बरसाए बम, 26 लोगों की मौत; फैली परमाणु हमले की अफवाह

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक बार फिर आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूस ने सोमवार को दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र के कोमिशुवाखा गांव में राहत सामग्री बांटने वाले केंद्र और उसके पास बने शेल्टर को निशाना बनाया। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के मुताबिक, इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने इस इलाके पर 10 गाइडेड बम गिराए। उनके मुताबिक, जिस स्कूल की इमारत में लोगों को मानवीय सहायता दी जा रही थी, वह भी हमले की चपेट में आ गई।

रूस को शांति नहीं, और खूनखराबा चाहिए : राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की जानकारी देते हुए रूस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह हमला साफ दिखाता है कि रूस तनाव कम करने के मूड में नहीं है। जेलेंस्की के मुताबिक, एक समय ऐसा था जब दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन इस हमले ने उन उम्मीदों को झटका दिया है।

सीजफायर खत्म होते ही फिर तेज हुए हमले : यह हमला ऐसे समय हुआ, जब यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन इलाके में लागू सीमित युद्धविराम सोमवार को खत्म हो गया। इस समझौते के तहत रूस और यूक्रेन ने अग्रिम मोर्चे के उन इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने की अनुमति दी थी, जहां हालात बेहद खराब हैं। इन इलाकों में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल थे। इसके अलावा सोमवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस की ओर से कई ड्रोन हमले किए जाने की भी जानकारी दी।

साइबर हमले के बाद लोगों के मोबाइल पर आए फर्जी अलर्ट : युद्ध के बीच रविवार देर रात यूक्रेन और सोमवार सुबह रूस में एक और परेशानी सामने आई। दोनों देशों के सरकारी इमरजेंसी अलर्ट ऐप हैक कर लिए गए। इसके बाद लोगों के मोबाइल पर फर्जी चेतावनी संदेश भेजे गए। यूक्रेन में लोगों को परमाणु हमले, रेडिएशन का स्तर बढ़ने और रासायनिक खतरे जैसी चेतावनियां मिलीं।

फ्लोरिडा विमान हादसा: को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजा था क्या आखिरी संदेश? 17 साल की उम्र में मिला पायलट लाइसेंस

फ्लोरिडा , एजेंसी। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए भीषण विमान हादसे से पहले 20 वर्षीय महिला को-पायलट नथालिया गडेल्हा फिल्गुएरास ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद की गुहार लगाई थी। हादसे से पहले की रेडियो रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज सुनी जा सकती है। वह बार-बार 'मे डे, मे डे' कहकर मदद मांग रही थीं। छोटा लीयरजेट विमान टेक्सास के ऑस्टिन से बहामास जा रहा था। इसी दौरान दक्षिण फ्लोरिडा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत में फिल्गुएरास ने बताया कि विमान पर बर्फ जम रही है। उस समय बाहर का तापमान माइनस 47 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने विमान में मध्यम स्तर के झटके आने की भी जानकारी दी। इन झटकों के कारण विमान करीब 700 फीट तक ऊपर-नीचे हो रहा





था। कुछ ही देर बाद उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, 'मे डे, मे डे!' इसके बाद उन्होंने बताया, 'हम 10,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे जा रहे हैं!' उन्होंने आगे कहा, 'हम ओवरस्पीड की स्थिति में हैं और 20,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं... हम जमीन से टकराने वाले हैं।' बाद में एडीएस-बी एक्सचेंज के फ्लाइट डेटा से पता चला कि हादसे से पहले लीयरजेट 60 विमान एक मिनट में 27,000 फीट नीचे गिर गया था। 20 साल की उम्र में कमर्शियल पायलट बनी थीं फिल्गुएरास स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, फिल्गुएरास ने 2023 में पायलट का लाइसेंस हासिल किया था। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी और वह वेस्ट बोका रैटन कम्युनिटी हाई स्कूल में सीनियर छात्रा थीं। ब्राजील मूल के परिवार से ताल्लुक रखने वाली फिल्गुएरास का परिवार फ्लोरिडा में रहता है। पायलट लाइसेंस मिलने के बाद वह स्थानीय मीडिया में भी चर्चा में आई थीं, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले ही निजी विमान उड़ाने का लाइसेंस हासिल कर लिया था। उनकी मां के मुताबिक, फिल्गुएरास पिछले नौ महीने से कमर्शियल पायलट के तौर पर काम कर रही थीं। उनकी मां कैमिला गडेल्हा कोर्टेलेटी ने सीएनएन ब्राजील से कहा, 'वह बहुत अच्छी लड़की थी। जिम्मेदार और मेहनती थी... वह को-पायलट थी और कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी।'

हादसे से पहले बॉयफ्रेंड को भेजा था क्या संदेश : फिल्गुएरास के पायलट लाइसेंस में जेट विमान उड़ाने की योग्यता दर्ज थी, लेकिन उन्हें उड़ान की कमान संभालने की अनुमति नहीं थी। उनके सौतेले पिता 44 वर्षीय थियागो कोर्टेलेटी ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि फिल्गुएरास को विमान उड़ाने का 1,300 घंटे का अनुभव था। उनके मुताबिक, हादसे से महज 10 मिनट पहले 20 वर्षीय फिल्गुएरास ने अपने बॉयफ्रेंड जस्टिन को मैसेज किया था। कोर्टेलेटी ने बताया, 'उसने बस इतना कहा था।

अगर डेमोक्रेट्स जीते तो मैं बन जाऊंगा 'मिस्टर वीटो' : ट्रंप

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो वह भविष्य में उनकी ओर से लाए गए किसी भी कानून को वीटो (अधिकार का इस्तेमाल कर रोकना) कर देंगे। सोमवार को जारी 'न्यूयॉर्क पोस्ट' के पॉडकास्ट 'पॉड फोर्स वन' में मिरांडा डिवाइन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं जीते, तो मैं हर चीज को वीटो कर दूंगा। मैं बस वीटो ही करता रहूंगा।' रविवार को प्रसारित एक प्रीव्यू क्लिप में ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं 'मिस्टर वीटो' बन जाऊंगा।' उन्होंने कहा कि एक-दो महीने तक लगातार वीटो करने के बाद, डेमोक्रेट्स 'खुद चलकर आएंगे और



एक समझौता करेंगे। तीसरे कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'अगर मुझे मौका मिलता, तो मैं फिर से चुनाव लड़ना पसंद करता, लेकिन संविधान की भाषा बहुत सख्त है। मैं जरूर लड़ना चाहता। हाल ही में एक पोल हुआ था जिसमें मैं बाकी सभी से काफी आगे था। मैं चुनाव लड़ना पसंद करता, लेकिन कोई बात नहीं। ' अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। 80 वर्षीय ट्रंप ने 2016 और 2024 में राष्ट्रपति पद जीता था। उन्होंने कहा, 'हमारे पास अभी दो साल से ज्यादा का समय बचा है। यह काफी लंबा समय होता है। इतने समय में बहुत कुछ किया जा सकता है, और आपने देखा ही है कि हमने अब तक क्या काम किया है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस जीतने के बाद उनके लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ जांच शुरू करते हैं, तो वह उन लोगों को पहले से ही 'माफी' (पार्डन) देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी, तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा... मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस कर दूंगा। मैंने जे6 (6 जनवरी की घटना) के मामले में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने उन पोल (सर्वे) को खारिज कर दिया जिनमें डेमोक्रेट्स को आगे दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि इन पोल्स में धांधली हुई है। मुझे तो लगता है कि कई पोल करने वाली एजेंसियां तो लोगों को सर्वे के लिए बाहर भेजती ही नहीं हैं। हो सकता है कि वे रिपब्लिकनों के बीच पोल न करते हों, लेकिन मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं रैलियों के आधार पर ऐसा कह रहा हूं।' ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर डेमोक्रेट्स हाउस, सीनेट और बाद में व्हाइट हाउस जीत जाते हैं, तो 'हमारा देश खत्म हो जाएगा। ज्यादातर पब्लिक पोल में हाउस जीतने के मामले में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी दिख रहा है। रविवार को जारी न्यू यॉर्क टाइम्स/सिएना के अंतिम पोल के अनुसार, कंसास, ओहियो, मेन, टेक्सास और मिशिगन में डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार 5 से 11 अंकों से आगे चल रहे हैं।

मेक्सिको: स्कूलों में बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे फोन, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

मेक्सिको सिटी , एजेंसी। मेक्सिको में अब स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू होने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद बच्चों और किशोरों को मोबाइल की लत, तनाव और पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने जैसी समस्याओं से बचाना है। हालांकि, देश के कई हिस्सों में माता-पिता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। मेक्सिको के कई इलाकों में संगठित अपराध और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में माता-पिता का कहना है कि अगर बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा तो किसी आपात स्थिति में वे उनसे संपर्क कैसे कर पाएंगे। सरकार ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले ने बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा के बीच बहस छेड़ दी है। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार की पहल का हिस्सा है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पूरे स्कूल समय के दौरान मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में छूट दी गई है। छात्र शिक्षक के निर्देश पर पढ़ाई से जुड़े काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा निजी आपात स्थिति, दिव्यांगता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में भी फोन के इस्तेमाल की अनुमति होगी। छात्र स्कूल आने-जाने के दौरान अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं। यानी प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य स्कूल के अंदर पढ़ाई



के समय मोबाइल के इस्तेमाल को रोकना है। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का डिजिटल उपकरणों पर निर्भर रहना कम होगा और वे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे।

सरकार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया : मेक्सिको सरकार का कहना है कि बच्चों और किशोरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। इनमें मोबाइल की लत, ध्यान की कमी, तनाव और बेचैनी जैसी समस्याएं शामिल हैं। देश के शिक्षा मंत्री मारियो डेलगाडो ने प्रतिनिधि सभा में कहा कि राष्ट्रपति शीनबाम की सरकार का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की लत और उससे पैदा होने वाली परेशानियों से बचाना है। सरकार इसी महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम भी लागू करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को नफरत फैलाने वाली पोस्ट, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और अन्य गैरकानूनी सामग्री हटानी होगी। सरकार का मानना है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के नुकसान से बचाने के लिए स्कूलों में मोबाइल पर नियंत्रण जरूरी है।

यूके में स्थायी निवास नियम: गृह मंत्रालय के फैसले से भारतीयों को लाभ, केयर वर्कर पर शबाना महमूद का रुख क्या?

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में स्थायी निवास से जुड़े नियम पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के नए फैसले से भारतीयों को लाभ होगा। केयर वर्कर से जुड़े इस नियम को लेकर गृह मंत्री शबाना महमूद अपने सख्त रुख से पीछे हटी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेशी केयर वर्कर के लिए स्थायी निवास की प्रतीक्षा अवधि को तीन गुना करने के अपने पहले के सख्त रुख से पीछे हट गई। इस कदम से हेल्थ एंड सोशल केयर वीजा मार्ग का उपयोग करने वाले कई भारतीयों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक साल तक चले सार्वजनिक परामर्श के बाद, महमूद ने संसद को बताया कि वह एक 'निष्पक्ष समझौते' पर पहुंची हैं। इसके तहत कोविड महामारी के बाद देश की सेवा करने वाले केयर वर्कर को पांच साल में स्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी।

कितने भारतीय लोगों को वीजा विस्तार का लाभ मिला: सोमवार को गृह कार्यालय ने इस साल के नवीनतम आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष में हेल्थ एंड सोशल केयर श्रेणी के तहत 1,04,555 वीजा विस्तार पाने वाले श्रमिकों में भारतीय सबसे आगे हैं। इनमें से अधिकांश अब अपनी अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) के लिए मूल रूप से निर्धारित पांच साल की समय-सीमा के भीतर पात्र



होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने एक बयान में कहा कि लोग एक ऐसी आव्रजन प्रणाली देखना चाहते हैं जो नियंत्रण, योगदान और नियमों का पालन करने वालों को पुरस्कृत करने पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव इसी सिद्धांत पर आधारित हैं और हमारे देश में विदेशी श्रमिकों के योगदान को मान्यता देते हैं। आव्रजन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं बर्नहैम ने कहा कि ब्रेग्जिट के बाद पिछली सरकार ने आव्रजन पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उन्होंने गृह सचिव के इस समस्या को संभालने के प्रयासों का पूरा समर्थन किया। उन्होंने दोहराया कि यह 'केवल निष्पक्ष' है कि देश में सबसे मूल्यवान योगदान देने वाले प्रवासियों को जल्दी स्थायी निवास का अवसर दिया जाए। अन्य भूमिकाओं में काम करने वालों को अधिक समय तक इंतजार करना होगा। जो लोग प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं या अवैध रूप से आते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा या उन्हें भी अधिक समय तक इंतजार करना होगा। गृह कार्यालय ने पुष्टि की है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे ब्रिटेन में केयर वर्कर के योगदान को देखते हुए, जो लोग अपने वीजा की शर्तों को पूरा करते हैं और सालाना कम से कम 25,000 पाउंड कमाते हैं, वे पांच साल के बाद स्थायी निवास कर सकेंगे। भारतीयों को कैसे मिलेगा लाभ और कौन जल्दी स्थायी निवास कर पाएगा? शबाना महमूद के माता-पिता ने कश्मीर से ब्रिटेन प्रवास किया था। उन्होंने अपने परिवार के अनुभव का उल्लेख किया। उन्होंने 'अर्जित स्थायी निवास' प्रवास योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। इन योजनाओं में अधिक आय वालों को स्थायी निवास के लिए तेज मार्ग से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केयर वर्कर वीजा मार्ग का भी 'दुरुपयोग' किया गया था। बेईमान और शोषणकारी कंपनियां ऐसे श्रमिकों को प्रायोजित कर रही थीं, जिनके लिए वास्तव में कोई नौकरी मौजूद नहीं थी। जो लोग पांच साल के स्थायी निवास के लिए योग्य नहीं हैं, जो कुल संख्या का लगभग एक चौथाई है, उन्हें एक नए पांच साल के वीजा के माध्यम से योगदान करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। गृह कार्यालय ने कहा है कि वे इन वीजा को पूरा करने के बाद ही स्थायी निवास के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सार्वजनिक सेवा कर्मियों पर भी लागू होगा, जो इसी अवधि के दौरान पहुंचे थे।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

गिडिपाबली में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान रोका, 10 लोग अब भी लापता

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा के कंधमाल जिले के भूस्खलन प्रभावित गिडिपाबली गांव में खराब मौसम और लगातार भूस्खलन के खतरे को देखकर बचाव अभियान को रोक दिया। हादसे में अब भी 10 लोग लापता हैं। प्रशासन के इस फैसले के बाद लापता लोगों के परिजनों ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंधमाल के जिलाधिकारी वेदभूषण ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार, लापता लोगों के शव करीब 30 फुट गहरे मलबे में दबे हो सकते हैं। घटनास्थल पर तीन बार भूस्खलन होने से हालात बेहद गंभीर हैं। मलबा हटाने के लिए विस्फोट करने पर फिर भूस्खलन होने और बचावकर्मियों की जान को खतरा होने की आशंका है। परिवारों की सहमति से फिलहाल अभियान रोकने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के अनुसार, यदि अगले दो-तीन दिनों में मौसम साफ रहता है, तब अभियान बंद करने से पहले एक बार फिर तलाश की जाएगी। राज्य सरकार ने चक्रवात अर्नब के कारण हुई भारी बारिश के बाद शुक्रवार को बचाव अभियान शुरू किया था। इसमें एनडीआरएफ, रेलवे की टीमों, आईआईटी विशेषज्ञों, श्वान दस्तों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली गई।

खूंटी में शर्मनाक वारदात : तीन नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोप में तीन करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार

खूंटी, एजेंसी। झारखंड के खूंटी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला गंभीर मामला सामने आया है, जहां दो सगी बहनों सहित तीन नाबालिग लड़कियों के साथ उनके ही करीबी रिश्तेदारों द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म करने सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना दो नवंबर को खूंटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। पुलिस के मुताबिक, एक पीड़िता ने अपने एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मुरहू में रहने वाली दोनों बहनों को आमंत्रित किया था। आरोप है कि पार्टी समाप्त होने के बाद तीनों आरोपी लड़कियों को बहला-फुसलाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गए और वहां उनके साथ यौन शोषण की इस घृणित वारदात को अंजाम दिया। खूंटी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषभ गर्ग ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी वयस्क हैं और पीड़ितों के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़िताओं के बयानों के आधार पर महिला पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी पीड़ित लड़कियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सभी पीड़िताओं की आवश्यक चिकित्सकीय जांच कराई है। फिलहाल, कानून के जानकारों और महिला पुलिस बल की देखरेख में मामले की आगे की गहन जांच की जा रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

एआई से छात्रा की अश्लील तस्वीर बनाने वाले बस चालक को 25 साल की सजा

बलिया, एजेंसी। उत्तरप्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने आठवीं कक्षा की छात्रा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल कर अश्लील तस्वीर बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्कूल बस के चालक संजीत कुमार को दोषी करार देकर 25 साल के कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना करीब डेढ़ साल पुरानी है। भीमपुरा थाने में पीड़ित छात्रा के पिता ने पिछले साल 7 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी संजीत कुमार स्कूल में अनुबंध पर वाहन चलाता था।

पीएम मोदी को खड़गे की चुनौती, राहुल गांधी से खुली बहस क्यों नहीं कर रहे?

राहुल गांधी ने कहा, 24 घंटे हो गए अभी तक जबाव नहीं आया

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर सवाल किया है कि वे वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर सवालों का सामना करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के खिलाफ दिमागी नक्सल जैसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने पोस्ट कर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की घेराबंदी की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता खड़गे का आरोप है कि आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर पांच बार अपना रुख बदला है। उन्होंने फॉर्म-6 का जिक्र कर दावा किया कि चुनाव आयोग के कुछ अन्य आयुक्तों ने इस फार्म को गैरकानूनी बताया था।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देश में तीन करोड़ घुसपैठियों के होने का दावा करते हैं, लेकिन इतने वर्षों तक इस पद पर रहने के बावजूद अवैध घुसपैठ रोकने में मोदी सरकार क्यों सफल नहीं हुई? खड़गे ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग और वोट बचाओ रैली का उल्लेख कर कहा कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को परेशान कर दिया हैं। उन्होंने संसद सत्र को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए। खड़गे के मुताबिक, बीते संसद सत्र के समाप्त होने के 83 दिन बाद सरकार विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संसद में आकर पत्रकारों के सामने सवालों का जवाब देने और राहुल गांधी के साथ खुली बहस करने की मांग की। इसके पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी चुनौती के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी पसंद का मंच और स्थान चुन सकते हैं। बहस के दौरान मीडिया और देश के युवाओं की मौजूदगी भी होनी चाहिए। उन्होंने बहस का मुद्दा देश विरोधी गतिविधियों और विदेशी ताकतों से संबंधों को बनाने की बात कही। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत बहस के निर्णायक हो सकते हैं।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों की मदद से



सत्ता में आने और उनके सहारे सत्ता में बने रहने के आरोप लगाए थे। उन्होंने भारत की वित्तीय व्यवस्था पर भी विदेशी ताकतों के प्रभाव का दावा किया था। यह राजनीतिक विवाद गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के बाद तेज हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

श्रीनगर में आग से 80 अस्थायी शेल्टर राख, कबाड़ा जमा करने वाले दो लोगों की मौत

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आग लगने से दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई और करीब 80 अस्थायी शेल्टर जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बेमिना के दुर्बल में सुबह-सुबह अस्थायी शेल्टर में लगी भीषण आग में दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आग आधी रात को लगी, जिसने तिरपाल और लकड़ी से बने करीब 80 अस्थायी शेल्टरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक टिपर को भी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया।



चश्मदीदों ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाने से पहले ही आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो लाशें मिलीं। मरने वाले दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रुप में हुई। दोनों बेमिना के दुर्बल में स्क्रैप इकट्ठा करने का काम करते थे। अधिकारियों ने कहा कि एफएसएल की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों शव पुलिस को सौंप दिए गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस ने इस घटना में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि करीब 80 से 95 फीसदी आग लगने की वजह इंसानी गतिविधियां होती हैं। बिना देखरेख के या ठीक से न बुझाए गए कैंपफायर आग लगने का एक मुख्य कारण हैं। गाड़ियों से या चलते समय लापरवाही से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, यार्ड का कचरा, कूड़ा या खेती/काट-छांट कर जलाए गए खेत जो काबू से बाहर हो जाते हैं, चेनसॉ, गाड़ियों, या सूखी सड़कों पर टो चेन खींचने से निकलने वाली चिंगारी, और गिरी हुई बिजली की लाइनें, ये सभी अचानक आग लगने के बड़े कारण हैं।

अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना मजबूरी है, मरवा सकते हैं खान सर

- ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद ने एक इंटरव्यू में लगाए गंभीर आरोप

पटना, एजेंसी। बिहार में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रौशन आनंद के बीच विवाद फिर चर्चा में है। रौशन आनंद ने एक इंटरव्यू में खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना उनकी मजबूरी है। रौशन आनंद ने दावा किया कि खान सर उन्हें भी मरवा सकते हैं और अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर बेहद धूर्त हैं और यदि उन्हें लगता है कि किसी की जान लेकर वह सुरक्षित रह सकते हैं, तो वह ऐसा भी कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आनंद ने 2 जून को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। उनके मुताबिक गोलीकांड सरकारी बॉडीगार्ड हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने खुद पर दर्ज प्राथमिकी को झूठा बताते हुए कहा कि 3 जून की सुबह करीब 4 बजे बिना उचित जांच के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आनंद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खान सर के खिलाफ लगाए गए पुराने आरोपों की जांच नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ना जीने की खुशी, ना मरने का गम। रौशन आनंद ने कहा कि अब उनकी जिंदगी भी इसी स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने अपने भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध मौत का जिक्र करते हुए खान सर पर गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि, खान सर इन आरोपों को पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं।

अब्दुल रहमान की जीत पर ओवैसी... अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएंगे

मिशीगन से सीनेट चुनाव जीतकर रखा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी । अमेरिका के मिशिगन में अब्दुलर हमान मोहम्मद अल-सैयद की सीनेट चुनाव में जीत ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी हैं। वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हैं, जिसकी गूंज भारत तक पहुंची और एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जीत को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए राजनीतिक पहचान मजबूत करने का संदेश बताया।

ओवैसी ने लिखा, एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब यूपी के अब्दुल को भी अपनी सियासी पहचान मज़बूत करनी होगी। संघियों ने अब्दुल को तंज़ में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं



बिछाएंगे। उनका यह बयान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक ताकत पहचानने और मजबूत करने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है।

बात दें कि मिस्र-अमेरिकी मूल के डॉक्टर और प्रगतिशील नेता अल-सैयद ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स के खिलाफ एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उनकी यह जीत अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस्लामोफोबिक हमलों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जिहादी तक कहा और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के भीतर से भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जब अगस्त में उनसे प्राइमरी में हारने वाली हेली स्टीवंस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार का समर्थन कर दिया।

जीत का दावा करने के बाद, अल-सैयद ने अपने भाषण में अमेरिकी व्यवस्था पर कॉरपोरेट कंपनियों और अरबपतियों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश में लोगों को राशन, पेट्रोल, घर या डॉक्टर को दिखाने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। अल-सैयद ने स्पष्ट किया कि करदाताओं का पैसा लोगों और उनके बच्चों पर खर्च होना चाहिए, न कि दूसरे देशों के बच्चों पर बम गिराने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की महानता अपनी कमियों को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हिम्मत दिखाने में है। उनकी यह जीत अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

पंजाब में इंसाफ की बात करने से पहले 1984 के मामले पर जवाब देना था

-राहुल गांधी की इंसाफ रैली को लेकर बीजेपी नेता ने बोला तीखा हमला

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बुधवार को संगरूर जिले में होने वाली इंसाफ रैली को लेकर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ था, उसे देश की जनता आज तक नहीं भूली है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी को पंजाब में इंसाफ की बात करने से पहले 1984 के मामले पर जवाब देना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि अच्छी बात तो यह होती कि राहुल गांधी इस मामले में पंजाब की जनता के सामने जवाब लेकर आते। ऐसे में राहुल गांधी जब पंजाब आकर राज्य के हक की बात करते हैं, तो उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल की ओर से पीएम मोदी को बहस की चुनौती दिए जाने पर पूनिया ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को करीब 55 साल तक शासन करने का अवसर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर आम नागरिक भी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, लेकिन पार्टी के पास जवाब नहीं होते। राहुल गांधी को पीएम मोदी से बहस करने से पहले अपनी ही पार्टी के भीतर देखना चाहिए और परखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी आम बीजेपी कार्यकर्ता के साथ भी बहस कर लें, तो उन्हें कांग्रेस से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

पूनिया ने कहा कि पंजाब कभी सुख-शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन 1984 की घटनाओं ने राज्य और देश के सामने गहरा जख्म छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि उन घटनाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए दिल्ली और हरियाणा की बीजेपी सरकारों ने प्रयास किए हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से 1 नवंबर को आयोजित रैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन 1984 में नरसंहार और कत्लेआम हुआ था, उसी दिन बड़ी रैली आयोजित करने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी, यह समझ से परे है। नई पीढ़ी को भी उस घटना के बारे में याद रखना चाहिए और पीड़ित समुदाय के साथ जो हुआ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब में बीजेपी के साथ अन्य पार्टियों के गठबंधन पर पूनिया ने कहा कि कुछ फैसलों के लिए अभी इंतजार करना चाहिए।



शेख हसीना ने बांग्लादेश के हालात पर जताई गहरी चिंता

-महिलाओं और बच्चों के साथ ही अल्पसंयकों की सुरक्षा खतरे में

नई दिल्ली, एजेंसी । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के वर्तमान हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है, हसीन ने आरोप लगाया है कि अगस्त 2024 में उनकी सरकार गिरने के बाद से राजनीतिक उत्पीड़न में वृद्धि हुई है और महिलाओं, बच्चों व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। एक ऑनलाइन संबोधन में हसीना ने दावा किया कि जुलाई से सितंबर के बीच 253 महिलाओं और लड़कियों, जिसमें 154 बच्चियां थीं, के साथ बलात्कार हुआ और 12 पीड़ितों की हत्या भी की गई। उन्होंने बताया कि मार्च से अब तक खसरे से 1,250 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने फैक्टरियों के बंद होने, बेरोजगारी, वसूली और हिंसा के कारण आम लोगों की बढ़ती मुश्किलों और कट्टरपंथी संगठनों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर की, उन्होंने चेतावनी देकर कहा कि ये घटनाक्रम बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर शेख हसीना ने बताया कि उनकी सरकार के दौरान बांग्लादेश में गरीबी की दर 41 से घटकर 18.6 प्रतिशत



हो गई थी। उन्होंने करीब 14 हजार सामुदायिक क्लीनिक स्थापित करने, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार लाने को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। हसीना ने 1997 के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते और 2017 में रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय देने जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया। हसीना ने जुलाई-अगस्त 2024 की हिंसा के दौरान निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश देने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग को रोक दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन में शामिल लोगों को कानूनी सुरक्षा क्यों दी गई, जबकि अवामी लीग के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमले हुए और उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ा। हसीना ने अपनी छवि खराब करने के लिए एआई से बनाई गई तस्वीरों, फर्जी खबरों और स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया, साथ ही हिंसा, मौतों, आगजनी और तोड़फोड़ की एक स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों, पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाने का दावा किया। अपने संबोधन के अंत में शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, लोकतांत्रिक देशों की सरकारों और मानवाधिकार संगठनों से बांग्लादेश के हालात पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, अवामी लीग पर लगी पाबंदियां हटाने, अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों को समान सुरक्षा प्रदान करने और एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की मांग की। हसीना ने हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की स्थापना पर भी जोर दिया।

शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिली, मुंबई के लिए रवाना

पुणे , एजेंसी । एनसीपी (एसपी) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है और अब उनकी हालत स्थिर है। वे सीधे अपने मुंबई स्थित आवास के लिए रवाना हो गए हैं। रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने पवार की सेहत को स्थिर और ठीक बताया। पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, बाबा अब काफी बेहतर हैं और हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। रूबी हॉल की पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनकी इतनी अच्छी देखभाल की। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। सांसद पवार को सोमवार को खांसी और सीने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था।

राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर सीएम हिमंत का पलटवार, यह बांग्लादेश या नेपाल नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी । कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि अगर वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस करना चाहते हैं, तब इसके लिए संसद का मंच चुनें। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भारत में राजनीतिक बहस संसद में होती है, न कि सड़क या किसी गली में होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश या नेपाल नहीं है।



दरअसल, राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी मंच पर आमने-सामने बहस करना चाहिए। वीडियो में राहुल गांधी हाथ में लाल गुलाब लेकर प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं देते नजर आए थे। राहुल के वीडियो पर प्रतिक्रिया देकर सीएम सरमा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लाल गुलाब को लेकर राहुल पर व्यंग्य कर कहा कि गुलाब वैलेंटाइन डे पर दिया जाता है, दीपावली पर नहीं। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सरमा ने राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाकर कहा कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और यदि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बहस करनी है, तब संसद से बेहतर मंच दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष संसद में मौजूद हैं और राहुल गांधी के परिवार के सदस्य भी संसद का हिस्सा हैं। इसके बाद बहस वहीं होनी चाहिए। सीएम सरमा ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर भी राहुल गांधी की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से विदेशी संबंधों पर सवाल पूछना चाहते हैं, तब संसद में इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने बोफोर्स और भोपाल गैस त्रासदी जैसे पुराने मामलों का जिक्र कर कहा कि बहस में कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जा सकते हैं।